

कीमतेँ और मौद्रिक प्रबन्धन

दिसंबर 2009 से थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) द्वारा मापित रूप में मुद्रास्फीति 7 प्रतिशत से अधिक के स्तर पर रही है। इस अवधि के दौरान खाद्य मुद्रास्फीति में विशेष रूप से वृद्धि हुई है जिसका कुल मुद्रास्फीति में योगदान औसतन एक तिहाई है। उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जिनमें खाद्य मुद्रास्फीति का अधिक योगदान है जो प्रायः समग्र डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक होती है। अब डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में मामूली कमी स्पष्टतः दिखाई दे रही है, किन्तु यह कमी काफी हद तक गैर खाद्य विनिर्मित उत्पादों की मुद्रास्फीति की दर में गिरावट के कारण हुई है। विश्वभर में मुद्रास्फीति का दबाव कम हुआ है। वर्ष 2012 के अंत में वैश्विक उपभोक्ता मूल्य में 3.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। नवम्बर 2012 के बाद के तीन महीनों के दौरान विकासशील देशों में भी मुद्रास्फीति की वार्षिक दर घटकर कर 5.4 प्रतिशत हो गई है। जो वर्ष 2011 में औसतन 7.2 प्रतिशत थी बेसलाइन परिदृश्य में ऊर्जा और गैर ऊर्जा वस्तुओं के लिए वर्ष 2013 में मुद्रास्फीति लगभग क्रमशः (-) 2.6 प्रतिशत और (-) 2.0 प्रतिशत होने से वैश्विक जिन्स मूल्यों में मामूली मुद्रास्फीति से भारत में भी व्यापार योग्य वस्तुओं की मुद्रास्फीति पर रोक लगेगी। मुद्रास्फीति को धारणीय रूप में कम करने के लिए मांग से नियंत्रित करने में प्रयासरत मौद्रिक नीति के अतिरिक्त, आपूर्ति पक्ष की अनुक्रियाएं आवश्यक होंगी और साथ ही चालू नीतिगत पहलों को भी किए जाने की आवश्यकता है।

मुद्रास्फीति-व्यापक रुझान

4.2 वित्त वर्ष 2012-13 की शुरुआत समग्र थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) मुद्रास्फीति के 7.50 प्रतिशत की स्थिति से हुई। दिसम्बर 2012 के अब तक के नौ महीनों के दौरान यह 7.18 से 8.07 प्रतिशत के रेंज में रही है। तथापि, प्रमुख सूचकांकों के संबंध में उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति जिसमें जनवरी 2011 के दौरान 4.92 से 7.65 प्रतिशत के रेंज में कमी आई है, में उसके बाद से वृद्धि होने लगी। वर्तमान वर्ष की अधिकांश अवधि के दौरान और औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आईडब्ल्यू) तथा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) की नई श्रंखला के रूप में मापित मुद्रास्फीति दो अंकों में बनी रही। कृषि श्रमिकों तथा ग्रामीण श्रमिकों के लिए भी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) गत दो महीनों में दो अंकों के स्तर पर पहुंच गए। (सारणी 4.1)

व्यापक जिन्स समूहों के स्तरों पर डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति-रुझान

4.3 समग्र डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति जो 2010-11 में औसतन 9.56 प्रतिशत और 2011-12 में 8.94 प्रतिशत थी, 2012-13 के पहले नौ महीनों (अप्रैल-दिसंबर) के दौरान घटकर 7.55 प्रतिशत हो गई। हालांकि दिसम्बर, 2012 में मुद्रास्फीति तीन वर्षों के निम्नतम स्तर पर 7.18 प्रतिशत थी यह गत बारह महीनों में 7-8 प्रतिशत की रेंज में रही। तथापि, इस स्थायी मुद्रास्फीति के लिए योगदान करने वाले विभिन्न जिन्स समूहों के सापेक्षिक महत्व में समय के अनुरूप बदलाव आया। पशु उत्पादों (अंडे, मांस और मछली) के मूल्यों में हुई स्थायी वृद्धि, अनाजों और सब्जियों के मूल्यों में वृद्धि तथा उर्वरकों (गैर यूरिया) के अंतरराष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि तथा डीजल के लागू मूल्यों में वृद्धि के कारण समय के साथ मुद्रास्फीति में भिन्न-भिन्न मात्रा में वृद्धि हुई। मूल्यों पर दबाव में हाल के

सारणी 4.1: भिन्न मूल्य सूचकांकों के अनुसार वार्षिक मुद्रास्फीति

माह	डब्ल्यूपीआई		सीपीआई-आईडब्ल्यू		सीपीआई-एनएस		सीपीआई-एएल		सीपीआई-आरएल	
	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13	2011-12	2012-13
अप्रैल	9.74	7.50	9.41	10.22	-	10.26	9.11	7.84	9.11	8.01
मई	9.56	7.55	8.72	10.16	-	10.36	9.63	7.77	9.63	8.11
जून	9.51	7.58	8.62	10.05	-	9.93	9.32	8.03	9.14	8.54
जुलाई	9.36	7.52	8.43	9.84	-	9.86	9.03	8.61	9.03	8.94
अगस्त	9.78	8.01	8.99	10.31	-	10.03	9.52	9.18	9.71	9.34
सित.	10.00	8.07	10.06	9.14	-	9.73	9.43	9.43	9.25	9.93
अक्तूबर	9.87	7.32	9.39	9.60	-	9.75	9.36	9.85	9.73	9.84
नवम्बर	9.46	7.24	9.34	9.55	-	9.90	8.95	10.31	9.14	10.47
दिसम्बर	7.74	7.18P	6.49	11.17	-	10.56	6.37	11.33	6.72	11.31
जनवरी	7.23		5.32		7.65		4.92		5.27	
फरवरी	7.56		7.57		8.83		6.34		6.68	
मार्च	7.69		8.65		9.38		6.84		7.19	
औसत	8.94	7.55*	8.39	10.00*	-	10.04*	8.19	9.17*	8.35	9.41*

स्रोत: आर्थिक सलाहकार कार्यालय, लेबर ब्यूरो, सीएसओ *औसत-अप्रैल-दिसम्बर, अ: अनंतिम

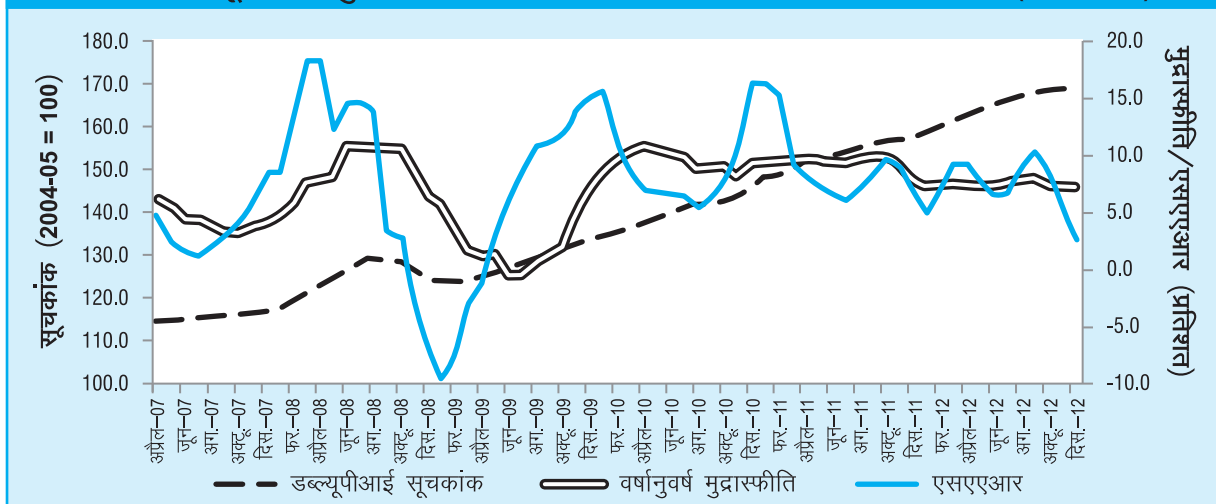
सीपीआई: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, आईडब्ल्यू: औद्योगिक कामगार, एएल: कृषि श्रमिक, आरएल: ग्रामीण श्रमिक; एनएस: नई श्रृंखला

महीनों के दौरान कमी हुई है जो समग्र डब्ल्यू पीआई के स्थिर बने रहने से प्रतीत होता है पिछले महीनों के दौरान अधिकांश जिंस समूहों में मूल्य परिवर्तन काफी कम रहा है जिससे यह विदित होता है कि व्यापक रूप से मुद्रास्फीति पर दबाव कम हुआ है और साथ ही मुद्रास्फीति का आवेग भी कम हुआ है जो डब्ल्यूपीआई सूचकांक के मौसम आधार पर समायोजित वार्षिक मुद्रास्फीति दर (एसएएआर) द्वारा ज्ञात होता है (चित्र 4.1)

4.4 मुद्रास्फीति का स्तर तथा तीन प्रमुख जिंस समूहों में इसके उतार-चढ़ाव में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ। प्राथमिक वस्तुएं जिनकी डब्ल्यूपीआई में 20.12 प्रतिशत हिस्सेदारी है, में मुद्रास्फीति 2011-12

की चौथी तिमाही में घटकर 6.7 प्रतिशत हो जाने के पश्चात् चालू वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में वृद्धि हुई तथा दिसंबर 2012 में यह 10.6 प्रतिशत के स्तर पर रही। ईंधन विद्युत प्रकाश और स्नेहक के समूह की जिंसें, जिनका थोक मूल्य सूचकांक में 14.91 प्रतिशत हिस्सेदारी है, में मुद्रास्फीति में चालू वर्ष के दौरान कुछ कमी हुई है। आधार प्रभाव के अतिरिक्त अप्रकमित पेट्रोलियम उत्पादों की मुद्रास्फीति में गिरावट के फलस्वरूप ही मुद्रास्फीति में यह कमी हुई है। इससे सितंबर 2012 में लागू डीजल के मूल्यों में वृद्धि के प्रभावों को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त हुई है। अंततः विनिर्मित उत्पादों, जिनकी डब्ल्यूपीआई में हिस्सेदारी 64.97 प्रतिशत

चित्र 4.1: डब्ल्यूपीआई, मुद्रास्फीति और मौसमी तौर पर समायोजित वार्षिक दर (एसएएआर)



सारणी 4.2: डब्ल्यूपीआई के प्रमुख श्रेणियों में तिमाही मुद्रास्फीति (%)

प्रमुख समूह सम्मिश्रित समूह	भारांश (%)	औसत (अप्रैल-मार्च)		2011-12				2012-13		
		2010 -11	2011 -12	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
		सभी वस्तुएं	100.0	9.56	8.94	9.60	9.71	9.01	7.50	7.54
प्राथमिक वस्तुएं	20.12	17.75	9.80	13.09	12.05	7.76	6.70	9.87	10.32	9.27
ईंधन एवं विद्युत	14.91	12.28	13.96	12.74	12.99	15.08	14.94	11.90	9.72	10.34
विनिर्मित उत्पाद	64.97	5.70	7.26	7.38	7.87	7.95	5.89	5.29	6.23	5.46
सम्मिश्र समूह										
सभी खाद्य	24.31	11.10	7.24	8.36	8.81	6.60	5.30	9.12	9.07	9.05
गैर खाद्य गैर-विनिर्मित पदार्थ	20.69	15.67	14.51	16.20	14.97	13.72	13.33	10.52	10.79	10.37
गैर खाद्य विनिर्मित पदार्थ	55.00	6.11	7.29	7.35	7.80	8.13	5.92	5.15	5.71	4.64

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

है, की मुद्रास्फीति में गिरावट आपेक्षिक रूप से तेज गति से हुई (सारणी 4.2)

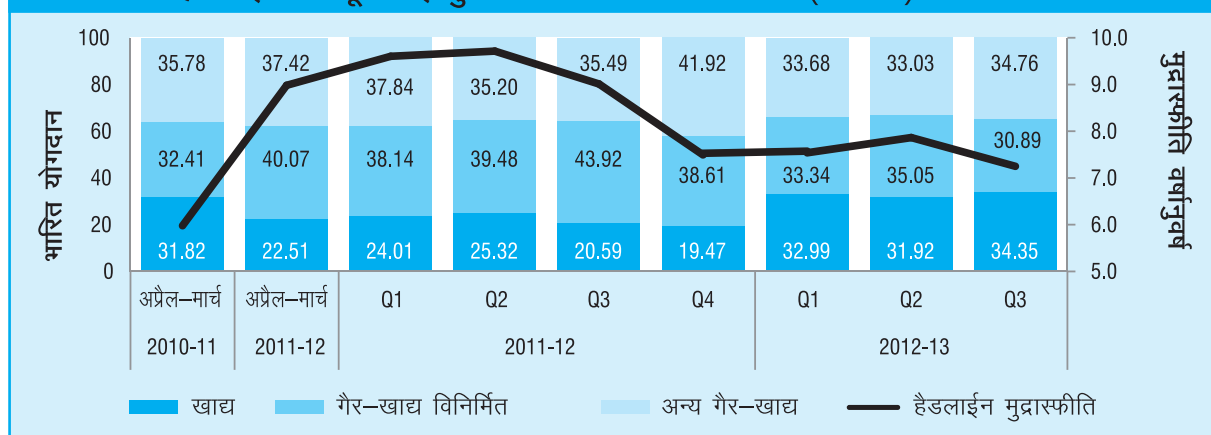
4.5 सम्मिश्र समूहों के संदर्भ में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति को अलग-अलग समूह में विभाजित करने पर यह विदित होता है कि खाद्य मुद्रास्फीति जिसमें प्राथमिक खाद्य वस्तुएं और विनिर्मित खाद्य उत्पाद (डब्ल्यूपीआई में 24.31 प्रतिशत भारांश) शामिल है, की 2012-13 की तीसरी तिमाही में 9.05 प्रतिशत थी, जो 2011-12 की चौथी तिमाही के 5.30 प्रतिशत की तुलना में पर्याप्त उच्च स्तर पर है। वास्तव में, खाद्य मुद्रास्फीति दिसंबर 2012 में 10.39 प्रतिशत पर पहुंचने से पूर्व जनवरी 2012 में घटकर 1.45 प्रतिशत हो गई थी। गैर-खाद्य, गैर विनिर्मित पदार्थों में चालू वर्ष के दौरान मुद्रास्फीति मामूली रही किन्तु दो अंकों के उच्च स्तर पर बनी रही जो मुख्यतः तिलहनों तथा ईंधन और विद्युत समूह में स्थित जिन्सों में अधिक मुद्रास्फीति के कारण है। तथापि, कोर मुद्रास्फीति जो गैर खाद्य विनिर्मित उत्पादों के लिए मुद्रास्फीति के संगत है, और जिसपर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुख्य रूप से

ध्यान दिया गया है, में 2011-12 की तीसरी तिमाही के उच्चतम स्तर से लगातार कमी प्रदर्शित हुई है। समग्र मुद्रास्फीति में इस सम्मिश्र समूह का योगदान भी 2011-12 की तीसरी तिमाही के 43 प्रतिशत से घटकर 2012-13 की तीसरी तिमाही में लगभग 30 प्रतिशत हो गया है। (चित्र 4.2) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए गए मौद्रिक उपायों के अलावा धातु रसायनों और वस्त्र उत्पादों के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मूल्यों में नरमी आने से कोर मुद्रास्फीति में कमी आई।

मूल्य रेंज के संदर्भ में जिन्सों का संवितरण

4.6 डब्ल्यूपीआई में शामिल सभी वस्तुओं में मुद्रास्फीति प्रभाव के संवितरण से यह ज्ञात होता है कि जिन जिन्सों पर मुद्रास्फीति का प्रभाव 20 प्रतिशत से अधिक हुआ है उनकी संख्या में तेजी से कमी आई है। 2011-12 की दूसरी तिमाही में जिन 72 जिन्सों पर जिनका मुद्रास्फीति में 13.8 प्रतिशत भारांश है, मुद्रास्फीति का प्रभाव 20 प्रतिशत से अधिक पड़ा है उनकी संख्या घटकर

चित्र 4.2: हेडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में भारत योगदान (प्रतिशत)



सारणी 4.3: मुद्रास्फीति रेंज के संदर्भ में डब्ल्यूपीआई जिन्सों का बारंबारता वितरण

	2010-11	2011-12	2011-12				2012-13		
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही (अ)
समग्र मुद्रास्फीति	9.56	8.94	9.60	9.71	9.01	7.50	7.54	7.87	7.25
मुद्रास्फीति रेंज में जिन्सों की संख्या ऋणात्मक	141	126	137	122	133	146	131	94	90
0 से 5 प्रतिशत	240	243	222	220	220	276	310	349	352
6 से 20 प्रतिशत	235	257	248	262	259	217	202	204	201
20 प्रतिशत से अधिक	60	50	69	72	64	37	33	29	33
मुद्रास्फीति रेंज में जिन्सों का भारांश									
ऋणात्मक	13.96	13.99	16.69	13.56	15.96	17.13	14.18	10.11	8.55
0 से 5 प्रतिशत	29.96	31.39	27.82	25.43	24.53	33.16	31.37	44.01	45.90
6 से 20 प्रतिशत	47.82	42.77	41.49	47.19	46.50	40.95	47.44	40.38	38.26
20 प्रतिशत से अधिक	8.26	11.85	13.99	13.81	13.01	8.77	7.01	5.50	7.29

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

अ: अनन्तिम

2012-13 की दूसरी तिमाही 29 हो गई तथा समग्र डब्ल्यू पीआई में उनका भारांश 5.5 प्रतिशत हो गया। डब्ल्यू पीआई में आधे से अधिक भारांश वाले लगभग दो-तिहाई जिन्सों में 5 प्रतिशत या कम की मुद्रास्फीति है (सारणी 4.3)। गत तीन तिमाहियों के दौरान वितरण संबंधी बदलाव में अधिक्व प्रतीत होता है। 20 प्रतिशत और इससे अधिक के मुद्रास्फीति रेंज में कम संख्या में जिन्सों के होने से यह ज्ञात होगा है कि मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों जैसे अर्थव्यवस्था को व्यापक आधार देने वाले उपायों के अतिरिक्त विशिष्ट जिन्सों पर केंद्रित कार्यनीतियों को अपनाने से भी मुद्रास्फीति को आगे नियंत्रण में रखने में सहायता प्राप्त होगी।

डब्ल्यूपीआई-खाद्य मुद्रास्फीति

4.7 प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित खाद्य उत्पादों दोनों के संबंध में मुद्रास्फीति में 2011-12 से बदलाव आया है। 2011-12 की चौथी तिमाही में समग्र खाद्य मुद्रास्फीति घट कर 5.30 प्रतिशत हो गई जो गत सात तिमाहियों की न्यूनतम तिमाही स्थिति है। प्राथमिक खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित खाद्य उत्पादों दोनों के संबंध में मुद्रास्फीति भी इस तिमाही के दौरान न्यूनतम स्तर पर रही (सारणी 4.4)। चालू वर्ष के दौरान इन दोनों समूहों के संबंध में मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई। तथापि, प्राथमिक खाद्य वस्तुओं में से प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थों के संबंध में मुद्रास्फीति कम हुई है, विशेषकर दूध तथा पशु-उत्पादों के मामले में भी ऐसा ही हुआ है जिसमें यह पर्याप्त तथा आनुक्रमिक रहा है। दालों के मामले में भी 2012-13 की तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में तेजी से कमी आई है। तथापि, चालू वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में खाद्य वस्तुओं

की मुद्रास्फीति में एक प्रमुख योगदान हुआ है। अनाज में मुद्रास्फीति जो 2011-12 की तीसरी तिमाही में घटकर 2.73 प्रतिशत हो गई थी, 2012-13 की तीसरी तिमाही में बढ़कर 17.05 प्रतिशत हो गई जिसका मुख्य कारण गेहूं, चावल और मक्के के मूल्य में वृद्धि होना है। अंशतः प्याज और आलू की मुद्रास्फीति में वृद्धि के कारण फलों और सब्जियों की मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई है। जबकि आलू के मामले में मूल्यों में वर्तमान वृद्धि एक संशोधन कहा जा सकता है क्योंकि इसमें मूल्यों में जनवरी 2012 में 2004-05 के आधार मूल्यों से भी नीचे गिरावट हो गई थी, गत दो महीनों के दौरान प्याज के मूल्यों में उछाल तथा मुद्रास्फीति देखी गई है।

4.8 2011-12 की चौथी तिमाही से विनिर्मित खाद्य उत्पाद समूह में डेयरी उत्पादों के मामले में मुद्रास्फीति में एक आनुक्रमिक और तेजी से कमी देखी गई है। मुद्रास्फीति में यह गिरावट दूध में मुद्रास्फीति की तुलना में तीव्रतर तथा अधिक स्पष्ट हुई है। अनाज मिल उत्पाद की मुद्रास्फीति में वृद्धि देखी गई है जिसका कारण गेहूं के मूल्यों में उछाल आना है जो इन जिन्सों के लिए मुख्य संघटक हैं 2010-12 में कम स्तर पर बने रहने के बाद चीनी में मुद्रास्फीति में वृद्धि का रुख प्रदर्शित हुआ है चालू वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाही में मूल्यों में विशेष तौर पर उछाल आया है। तथापि गत दो महीनों में चीनी के मूल्यों में कुछ कमी आई है इसके भावी मूल्यों में भी मामूली स्तर का मुलायम रूझान पता चलता है। हालांकि खाद्य तेलों की मुद्रास्फीति स्थिर बनी हुई है हालांकि यह उच्च स्तर पर है पर चालू वित्त वर्ष में खलियों की मुद्रास्फीति में भी वृद्धि हुई है। मौसमी आधार पर समायोजित मासिक डब्ल्यूपीआई श्रृंखला से ज्ञात खाद्य मुद्रास्फीति की गति से मुद्रास्फीति में मृदु वृद्धि रूझान का पता चलता है। (चित्र 4.3)

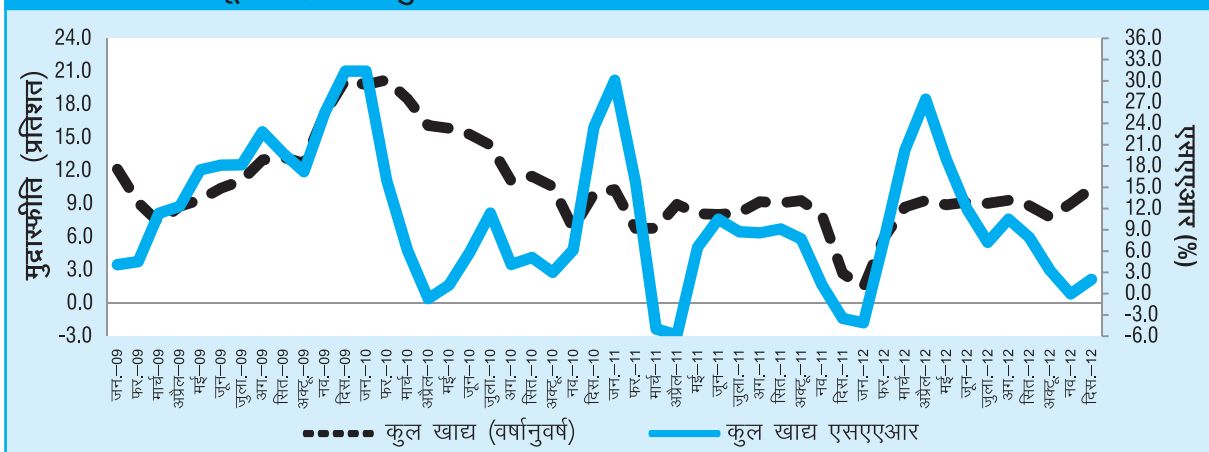
सारणी 4.4 : डब्ल्यू पी आई खाद्य मुद्रास्फीति के उपघटक (%)

प्रमुख समूह सम्मिश्रित समूह	भारांश (%)	औसत (अप्रैल-मार्च)		2011-12				2012-13		
		2010-	2011-	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
		11	12							
खाद्य मुद्रास्फीति	24.31	11.10	7.24	8.36	8.81	6.60	5.30	9.12	9.07	9.05
(क) खाद्य वस्तुएं	14.34	15.60	7.30	8.83	9.14	6.34	5.05	10.82	9.18	8.76
गैर प्रोटीन खाद्य पदार्थ	7.97	12.33	4.79	11.50	9.50	1.96	-2.88	8.00	6.23	7.54
अनाज	3.37	5.26	3.87	5.08	4.83	2.73	2.90	6.36	11.06	17.05
फल और सब्जियां	3.84	16.44	6.45	16.11	14.93	1.71	-5.26	14.40	5.30	3.98
अन्य खाद्य पदार्थ (चाय और कॉफी)	0.18	-7.25	18.97	22.62	20.90	18.43	14.21	10.01	15.25	13.10
कॉन्डिमेंटान तथा मसाले	0.57	33.56	-2.65	14.47	0.49	-3.83	-18.07	-18.18	-12.48	-15.99
प्रोटीन खाद्य पदार्थ	6.37	19.78	10.32	5.78	8.72	11.75	14.85	14.28	12.66	10.13
दालें	0.72	3.20	2.52	-8.32	-3.03	12.95	9.65	16.2	30.68	18.84
दूध	3.24	20.13	10.31	6.84	10.15	11.02	13.08	11.56	7.05	6.13
अंडे, मांस और मछली	2.41	25.51	12.73	9.17	10.64	12.32	18.55	17.12	14.63	12.47
(ख) खाद्य उत्पाद	9.97	3.72	7.12	7.52	8.19	7.07	5.76	6.02	8.85	9.59
डेयरी उत्पाद	0.57	9.56	12.85	6.04	12.11	17.94	15.28	9.38	4.09	-1.13
संसाधित खाद्य	0.36	5.05	9.72	7.22	8.87	10.55	12.15	8.12	2.47	1.15
अनाज मिल उत्पाद	1.34	5.67	0.27	2.80	0.81	-0.30	-2.10	-0.55	3.90	9.48
बेकरी उत्पाद	0.44	8.60	0.75	-0.58	0.40	1.43	1.74	2.12	2.13	3.62
चीनी, गुड़ एवं खांडसारी	2.09	-0.88	4.50	3.74	5.41	5.49	3.36	5.27	14.50	14.29
खाद्य तेल	3.04	5.43	12.55	14.92	14.45	12.22	9.00	10.35	10.82	9.59
सब्जियां	0.49	0.79	3.95	3.91	6.85	1.60	3.63	12.60	25.90	24.41
संसाधित चाय एवं कॉफी	0.71	3.48	4.55	11.19	4.77	-3.16	6.11	-1.98	-0.71	7.77
नमक	0.05	2.67	0.84	-6.70	1.47	3.73	5.42	5.51	5.51	1.72
अन्य खाद्य उत्पाद	0.88	4.72	11.54	9.22	13.92	14.48	8.69	6.15	1.89	3.57

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

अ: अनन्तिम

चित्र 4.3: डब्ल्यूपीआई खाद्य मुद्रास्फीति गति



डब्ल्यूपीआई-गैर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में मुद्रास्फीति

4.9 गैर खाद्य गैर विनिर्माण सम्मिश्र समूह जिन्सों का एक विसमांग मिश्रण है जिसमें खनिज पदार्थों और ईंधन और विद्युत के व्यापक समूह की जिन्सों सहित गैर खाद्य प्राथमिक वस्तुएं शामिल हैं। एक सम्मिलित स्तर पर इस सम्मिश्र समूह में मुद्रास्फीति 2011-12 की पहली तिमाही के शीर्ष से कुछ कमी प्रदर्शित हुई है तथापि समग्र स्तर दो अंको के स्तर पर बना हुआ है। इस सम्मिश्र समूह के भीतर जिन्स समूहों में मुद्रास्फीति में व्यापक अंतर रहा है। गैर खाद्य प्राथमिक वस्तुओं के मामले में मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट और लगभग उसी तेजी से उछाल प्रदर्शित हुआ है। तथापि, मुद्रास्फीति में तेजी से गिरावट और लगभग उसी तेजी से उछाल के कारण भिन्न थे। कपास और रेशों में 2011-12 की पहली तिमाही में 62.7 प्रतिशत की मुद्रास्फीति रही किंतु उसी वर्ष चौथी तिमाही तक यह ऋणात्मक हो गई। 2011-12 में कपास के उत्पादन में तेज वृद्धि और अवमंदक वैश्विक दशाओं के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई। अन्य गैर खाद्य प्राथमिक वस्तुओं में 2010-11 में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई जो काफी हद तक गन्ना और रबर के मूल्यों में वृद्धि के कारण हुआ। 2011-12 में ग्वार सीड जिस पर प्रयोग फ्रैकिंग हेतु किया जाता है, इस समूह में मुद्रास्फीति का प्रमुख कारक रहा। जिसमें मुद्रास्फीति की दर 155 प्रतिशत रही।

तिलहनों के मूल्य में भी सतत वृद्धि बनी रही। खनिज पदार्थों में मुद्रास्फीति का अपरिष्कृत पेट्रोलियम के मूल्य पर प्रभाव पड़ा। सभी राज्यों में बिजली के मूल्य में वृद्धि से ईंधन और विद्युत समूह की जिन्सों में चालू वर्ष की दूसरी और तीसरी तिमाहियों में मुद्रास्फीति में वृद्धि हुई। अप्रक्रमिक पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप रहा तथा 2011-12 की तीसरी तिमाही में शीर्ष से मुद्रास्फीति में गिरावट हुई। 2012-13 की तीसरी तिमाही में प्रक्रमित पेट्रोलियम उत्पादों की मुद्रास्फीति में वृद्धि डीजल के मूल्य में वृद्धि के कारण हुई (सारणी 4.5)। डीजल के मूल्यों में जनवरी में एक बार फिर संशोधन किया गया तथा इस संशोधन का मुद्रास्फीति पर प्रभाव जनवरी 2013 के थोक मूल्य सूचकांक में प्रतिबिंबित होगा। हालांकि इससे मुद्रास्फीति भी घटेगी तथा राजकोषीय समेकन में योगदान के द्वारा इसका दीर्घकाल में मूल्य पर संयतकारी प्रभाव पड़ेगा।

4.10 एसएएआर पर आधारित इस विसमांग समूह के लिए मुद्रास्फीति की गति एक अधोमुखी गति पथ को दर्शाती है। स्थिर या धीमी गति से बढ़ रहे अपरिष्कृत तेल मूल्यों तथा अन्य उत्पादों के संबंध में मामूली मुद्रास्फीति को देखते हुए स्थिति में सुधार की आशा है (चित्र 4.4)

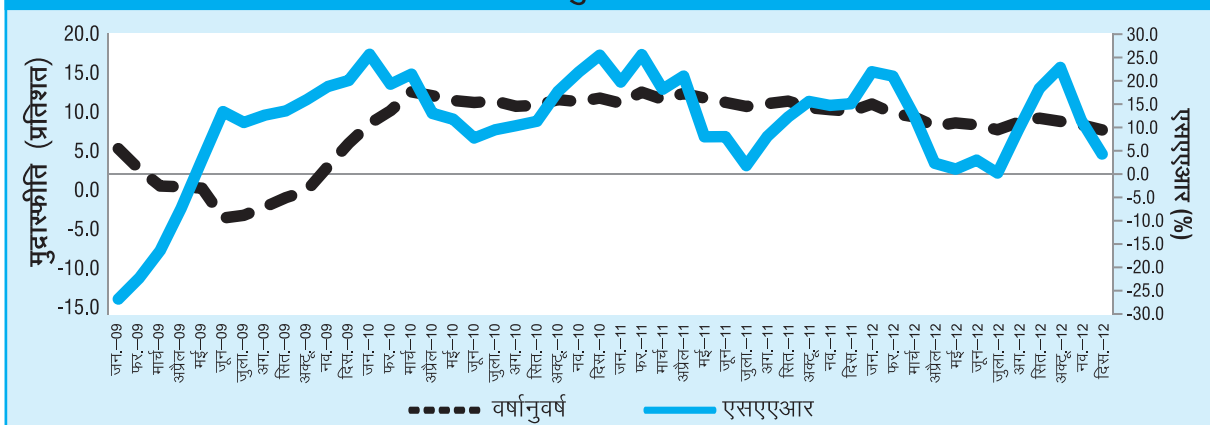
सारणी 4.5 : डब्ल्यूपीआई का उपघटक-गैर खाद्य मुद्रास्फीति (%)

घटक/ उपघटक	भारांश (%)	औसत (अप्रैल-मार्च)		2011-12				2012-13		
		2010- 11	2011- 12	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही (अ)
		गैर खाद्य	20.69	15.67	14.51	16.20	14.97	13.72	13.33	10.52
(क) गैर खाद्य वस्तुएं	4.26	22.33	9.65	22.23	16.16	4.15	-0.89	5.64	12.60	12.88
रेशे	0.88	41.69	10.09	62.69	29.78	1.39	-26.05	-20.84	1.04	-1.77
तिलहन	1.78	4.71	12.33	11.64	15.08	10.79	11.86	18.11	27.84	29.18
अन्य गैर खाद्य वस्तुएं	1.39	37.26	10.52	14.72	12.20	7.93	7.77	16.07	6.82	6.19
(ख) खनिज	1.52	24.82	26.60	25.48	24.48	23.67	32.52	11.66	13.51	6.61
धात्विक खनिज	0.49	44.70	10.10	11.70	7.00	4.91	16.74	9.70	12.51	6.33
अपरिष्कृत पेट्रोलियम	0.90	11.82	45.19	40.60	43.76	44.93	51.02	12.85	13.44	5.23
(ग) ईंधन और विद्युत	14.91	12.28	13.96	12.74	12.99	15.08	14.94	11.90	9.72	10.34
कोयला	2.09	5.68	15.52	13.25	13.25	13.25	21.97	13.92	13.92	13.92
खनिज तेल	9.36	16.00	16.85	16.05	16.49	18.84	16.02	12.23	7.20	8.93
प्रशासित पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	6.32	15.12	10.43	8.99	10.94	10.87	10.85	10.00	2.67	11.73
गैर-प्रशासित पेट्रोलियम, तेल और स्नेहक	3.04	17.47	27.43	27.62	26.18	32.36	23.89	15.35	14.17	4.95
विद्युत	3.45	5.38	1.64	0.27	-0.32	2.63	4.00	8.56	16.52	13.16

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय

अ: अनन्तिम

चित्र 4.4: गैर-खाद्य गैर-विनिर्मित पदार्थों में मुद्रास्फीति की गति



डब्ल्यूपीआई-गैर खाद्य विनिर्मित पदार्थ

4.11 गैर खाद्य विनिर्मित पदार्थों में मुद्रास्फीति जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कोर मुद्रास्फीति-कहा गया है, नवंबर 2011 में 8.35 प्रतिशत से घटकर दिसंबर 2012 में 4.24 प्रतिशत हो गया। गैर-खाद्य विनिर्माण समूह में पेय पदार्थ और तंबाकू उत्पाद, शाल एवं काष्ठ उत्पाद, रसायन तथा रासायनिक उत्पादों में 2012-13 की तीसरी तिमाही में 6 प्रतिशत की मुद्रास्फीति देखी गई। विनिर्माण के सभी प्रमुख खंडों में मुद्रास्फीति में कमी दिखाई दी। तथापि, मशीन एवं परिवहन उपकरणों में मुद्रास्फीति आमतौर पर कम स्तर पर बनी रही (सारणी 4.6)

4.12 गैर खाद्य विनिर्माण (चित्र 4.5) के एसएएआर से भी अधोमुखी गति प्रदर्शित होती है। यूरिया को छोड़कर गैर-खाद्य विनिर्मित उत्पाद पूरी तरह से व्यापार योग्य होते हैं और इस कारण वैश्विक मूल्य रुझानों का इन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। 2013 में वैश्विक जिन्स मूल्यों में कमी होने तथा 2014 में लगभग स्थिर बने रहने (बाक्स 4.3) से गैर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में मुद्रास्फीति में कुछ और कमी हो सकती है।

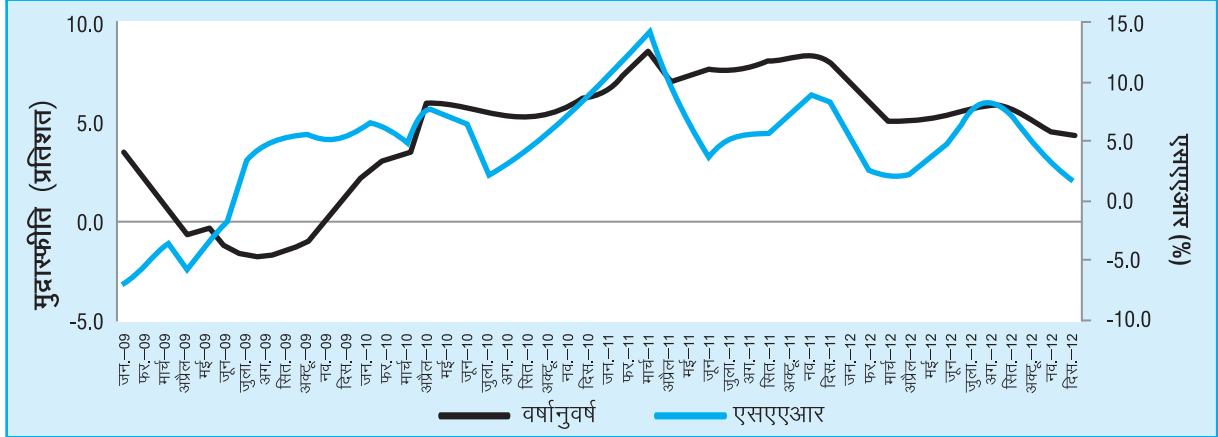
4.13 कोर मुद्रास्फीति के भीतर पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में मुद्रास्फीति की गति मंद बनी रही। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के संबंध में मुद्रास्फीति जो प्रायः कोर मुद्रास्फीति से अधिक होती है, में 2011-12 की तीसरी तिमाही से संयतकारी प्रभाव दिखाई देने

सारणी 4.6 : डब्ल्यूपीआई खाद्य-भिन्न निर्माण मुद्रास्फीति के उप-घटक (प्रतिशत)

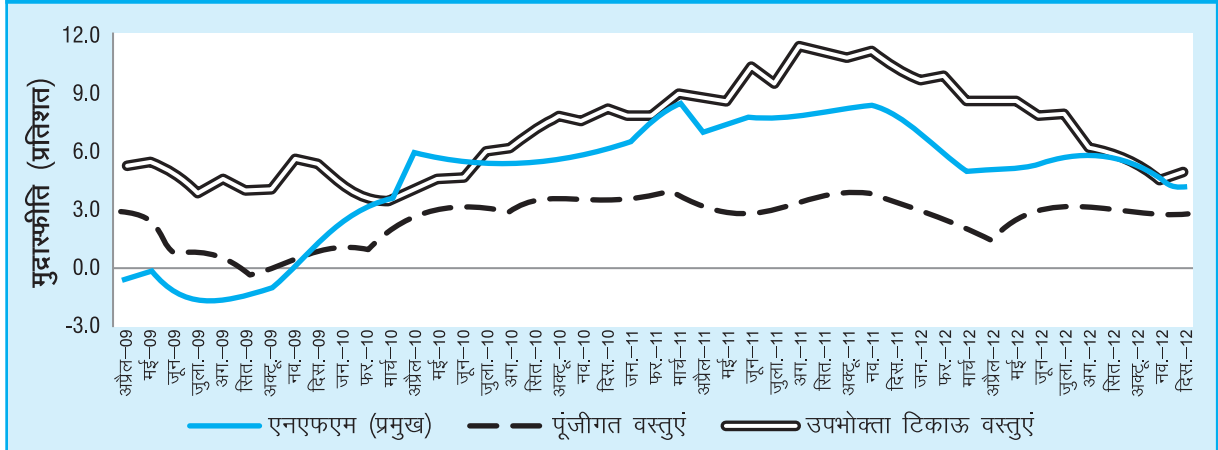
घटक/ उपघटक(%)	भारांश	औसत (अप्रैल-मार्च)		2011-12				2012-13		
		2010-11	2011-12	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही (अ)
गैर-खाद्य मुद्रास्फीति	55.00	6.11	7.29	7.35	7.80	8.13	5.92	5.15	5.71	4.64
पेयपदार्थ तथा तम्बाकू उत्पाद	1.76	7.36	11.67	10.01	13.23	13.32	10.21	7.79	6.76	7.89
वस्त्र	7.33	12.08	7.46	15.78	9.69	6.14	-0.78	-2.78	2.86	4.49
लकड़ी और लकड़ी से बने पदार्थ	0.59	3.97	8.09	5.87	8.88	8.91	8.70	6.67	5.92	6.03
कागज और कागज से बने पदार्थ	2.03	5.33	5.39	7.51	5.53	5.30	3.30	2.21	2.86	3.35
चमड़ा और चमड़े से बने पदार्थ	0.84	-0.99	2.32	0.16	0.91	2.71	5.61	3.73	3.98	2.18
रबर और प्लास्टिक से बने पदार्थ	2.99	6.68	5.97	8.56	7.70	5.67	2.23	1.88	2.85	3.24
रसायन और उत्पाद	12.02	5.34	8.61	7.45	8.71	9.93	8.36	7.24	7.63	6.09
गैर-धातु खनिज उत्पाद	2.56	2.68	5.73	3.91	4.12	7.65	7.23	7.13	9.22	5.44
मूल धातु, लौह अयस्क एवं उत्पाद	10.75	8.67	11.06	8.46	11.58	13.19	10.97	10.62	8.39	4.68
मशीनरी और टूल	8.93	2.82	3.11	2.96	3.20	3.41	2.88	2.50	2.91	2.52
परिवहन, उपकरण	5.21	3.02	3.52	2.16	4.07	4.54	3.34	3.83	3.80	4.34

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय अ: अनन्तिम

चित्र 4.5: गैर-खाद्य विनिर्मित पदार्थों में मुद्रास्फीति की गति



चित्र 4.6: प्रमुख, उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं के लिए डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति



लगे हैं और तभी से कोर मुद्रास्फीति के स्तरों को क्रमशः अभिसरित करते रहे हैं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जिनमें मांग रुचि संवेदी है, के संबंध में मुद्रास्फीति में कमी संभवतः मौद्रिक नीति के प्रभाव को प्रदर्शित करती है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

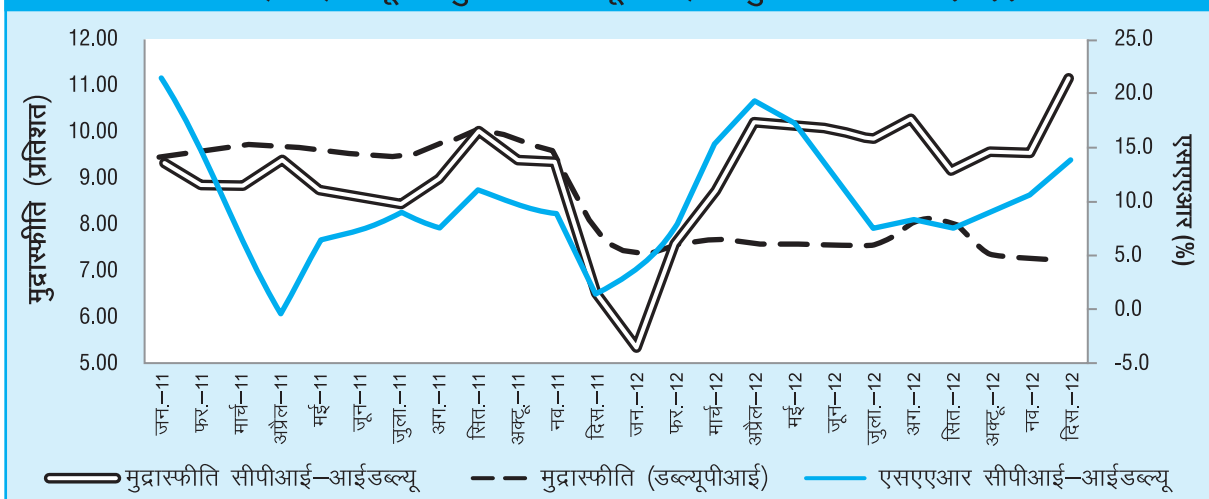
सीपीआई-आई डब्ल्यू

4.14 भारत में, नीति निर्माताओं सहित अन्य सभी का अधिकांश ध्यान समग्र डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति पर केंद्रित होता है। डब्ल्यूपीआई श्रृंखला में व्यापक प्रकार की वस्तुएं जिन्हें शामिल होती हैं तथा जिन्हें का डब्ल्यूपीआई में भारांश राष्ट्रीय लेखों से ज्ञात किए जाते हैं। व्यापक कवरेज के कारण अंतर्निहित अर्थव्यवस्था व्यापक मुद्रास्फीति बेहतर रूप में परिलक्षित होती है। कुछ अर्थशास्त्री एनएफएम डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति (या समग्र डब्ल्यूपीआई) के बजाय उपरोक्त मूल्य मुद्रास्फीति को ज्ञात करने के लिए केंद्रीय बैंक से आंकड़े प्राप्त करना अधिक पसंद करेंगे इसका कारण है कि प्रत्येक उपभोक्ता को केंद्रीय बैंक का कुछ न कुछ अनुभव होता है। इसके अतिरिक्त, व्यापक और स्थायी सीपीआई मुद्रास्फीति से जनता में उच्च मुद्रास्फीति संबद्ध प्रत्याशा उत्पन्न हो सकेगी।

4.15 जनवरी 2011 में नई सीपीआई श्रृंखला आरंभ किए जाने से पूर्व केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय के समक्ष 3 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक थे, ये सभी सूचकांक उपभोक्ताओं के एक विशिष्ट वर्ग से संबंधित थे। औद्योगिक कामगारों के लिए सीपीआई जो मुख्य रूप से वेतन निर्धारण सांख्यिकी को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, अनेक अर्थशास्त्रियों द्वारा अधिमानित सीपीआई सूचकांक रहा है। अगस्त 2010 से मार्च 2012 के दौरान मुद्रास्फीति में कमोबेश इसी प्रकार का रुख प्रतीत होता है चाहे इसे डब्ल्यूपीआई के संदर्भ में मापा जाए या फिर सीपीआई-आईडब्ल्यू के संदर्भ में, तथापि, इन दो मापों के बीच हाल के महीनों में लगभग 2 प्रतिशत बिंदु अंतराल (प्वाइंट गैप) ज्ञात हुआ है। इसी समय, इसकी आवधिकता विहीन श्रृंखला द्वारा मापित रूप में सीपीआई-आईडब्ल्यू की गति से हाल के महीनों में डब्ल्यूपीआई स्थायी वस्तुएं और डब्ल्यूपीआई खाद्य वस्तुएं के संगत मुद्रास्फीति में उल्लेखनीय कमी का पता चलता है। (चित्र 4.7)।

4.16 सीपीआई-आईडब्ल्यू के अवयवों की ओर आते हुए खाद्य समूह के संबंध में मुद्रास्फीति 2011-12 की चौथी तिमाही में घटकर 4.52 प्रतिशत होने के बाद वृद्धि प्रदर्शित हुई तथा 2012-13 के गत तीन तिमाहियों में यह दो अंकों में पहुंच गई है। ईंधन और प्रकाश तथा पान सुपारी और तंबाकू के व्यापक समूह के संबंध में मुद्रास्फीति भी गत सात तिमाहियों में दो अंकों में रही है।

चित्र 4.7: सीपीआई-आईडब्ल्यू के मुकाबले डब्ल्यूपीआई में मुद्रास्फीति और एसएएआर



सारणी 4.7: औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-आई डब्ल्यू) में मुद्रास्फीति

प्रमुख समूह	भारांश	2010-11	2011-12				2012-13		
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
सामान्य	100	10.45	8.91	9.16	8.39	7.17	10.14	9.76	10.1
खाद्य समूह	46.2	9.89	7.58	7.29	6.05	4.52	10.57	11.49	11.41
पान, सुपारी, तंबाकू और मादक वस्तुएं	2.27	12.42	13.91	15.23	16.87	15.21	14.9	15.13	14.94
ईंधन और प्रकाश	6.43	9.81	13.73	14.17	15.37	17.82	18.97	12.06	12.8
गृह-निर्माण सामग्रियां	15.27	21.12	12.17	10.95	10.95	8.96	8.96	6.73	6.73
वस्त्र, बिछावन और जूते	6.57	6.73	12.94	14.43	15.61	13.11	10.79	9.35	8.44
विविध समूह	23.26	5.26	6.75	7.73	8.03	7.05	7.35	7.57	8.61
गैर खाद्य	53.8	11	10.23	11.01	10.75	9.77	9.73	8.11	8.84

स्रोत: श्रम ब्यूरो

सारणी 4.8: नई श्रृंखला के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एनएस) में तिमाही मुद्रास्फीति 2010=100

क्षेत्र	समूह	भारांश (%)	2011-12 चौथी तिमाही	2012-13		
				पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
ग्रामीण	सामान्य	100.00	8.11	9.63	9.82	10.20
	खाद्य	56.59	6.01	10.10	11.62	12.27
	गैर खाद्य	43.41	10.86	9.03	7.53	7.59
शहरी	सामान्य	100.00	9.33	11.02	10.00	9.86
	खाद्य	35.81	6.76	11.13	12.16	11.74
	गैर खाद्य	64.19	10.81	10.95	8.79	8.81
संयुक्त	सामान्य	100.00	8.62	10.18	9.87	10.07
	खाद्य	47.57	6.25	10.47	11.81	12.10
	गैर खाद्य	52.43	10.8	9.92	8.13	8.26

स्रोत: सीएसओ अ: अनंतिम

2011-12 की पहली तिमाही से गृह क्षेत्र में मुद्रास्फीति में कमी आई है। (सारणी 4.7)

4.17 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने जनवरी 2011 में सीपीआई की एक नई श्रृंखला आरंभ की। नई श्रृंखला का व्यापक भौगोलिक प्रसार है और इसमें 310 नगरों और 1181 गांवों को कवर किया गया है। उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण आंकड़ों (2004-05) से प्राप्त आरंभिक स्कीम लागू किए जाने से नई श्रृंखला का स्वरूप अखिल भारतीय है। चूंकि यह श्रृंखला पूर्णतः नई है, अतः अभी केवल 12 महीनों की मुद्रास्फीति संख्या उपलब्ध है। नई सीपीआई श्रृंखला के व्यापक खाद्य और गैर खाद्य भारांश कमोबेश सीपीआई-आई डब्ल्यू से सुमेलित होते हैं। हालांकि कमी-बेशी के बिंदु उभयनिष्ठ है, किंतु नई श्रृंखला के संबंध में समग्र खाद्य मुद्रास्फीति सीपीआई-आईडब्ल्यू की तुलना में अधिक है। (सारणी 4.8)

मुद्रास्फीति क्यों बनी रही?

4.18 प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों विशेषकर मांस, मछली और अंडे; तथा सब्जियों और फलों में मुद्रास्फीति बनी रही जिसका कारण लोगों की भोजन संबंधी आदतों में बदलाव आना तथा आपूर्ति संबंधी बाधाओं का होना है। निजी अंतिम उपभोक्ता व्यय (पीएफसीई)

संबंधी राष्ट्रीय लेखाओं से प्राप्त दीर्घकालिक श्रृंखला आंकड़ों से प्रतिव्यक्ति उपभोक्ता में ढांचागत बदलाव का पता चलता है (सारणी 4.9)। विगत समय के दौरान कुल खपत में खाद्य पदार्थों की खपत की हिस्सेदारी में कमी आई है जो 1950-1960 के दौरान के औसतन 51.34 प्रतिशत से घटकर 2007-2012 के दौरान औसतन 27.82 प्रतिशत हो गई है। 1950-2012 के दौरान खाद्य खपत में प्रति व्यक्ति 0.94 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि हुई है जो इस अवधि में खपत में औसतन 1.84 प्रतिशत समग्र वृद्धि की तुलना में पर्याप्त कम है। प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की खपत में, जो पीएफसीई में हुई वृद्धि की तुलना में अधिक मदद से बढ़ रही है, 1950-2012 के दौरान 1.50 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित हुई है जो खाद्य पदार्थों पर समग्र व्यय में वृद्धि की तुलना में अधिक रही है। अतः समग्र खाद्य व्यय के भीतर प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थों की भागीदारी 1950-1960 के 26.28 प्रतिशत से बढ़कर 2007-2012 के दौरान 33.71 प्रतिशत हो गई (चित्र 4.8)

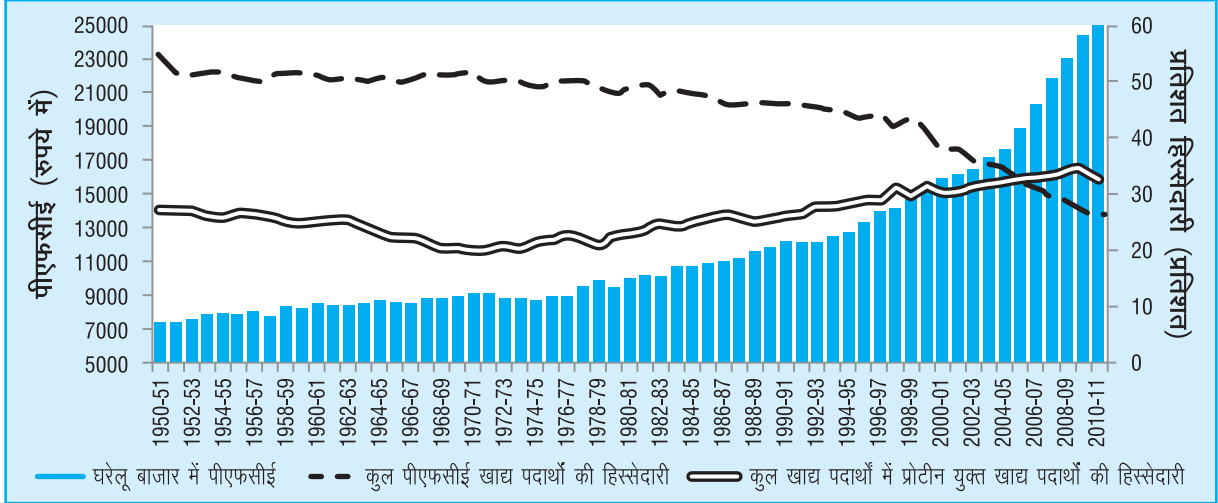
पीएफसीई

4.19 अन्य वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में खाद्य पदार्थों में पाई गई दीर्घकालिक गिरावट आय के बढ़ते स्तरों से जुड़ी हुई है (चित्र 4.9)। वर्ष 1950 से 2011 के दौरान खाद्य भिन्न वस्तु समूह के लिए प्रति व्यक्ति व्यय में वार्षिक औसत वृद्धि 2.40

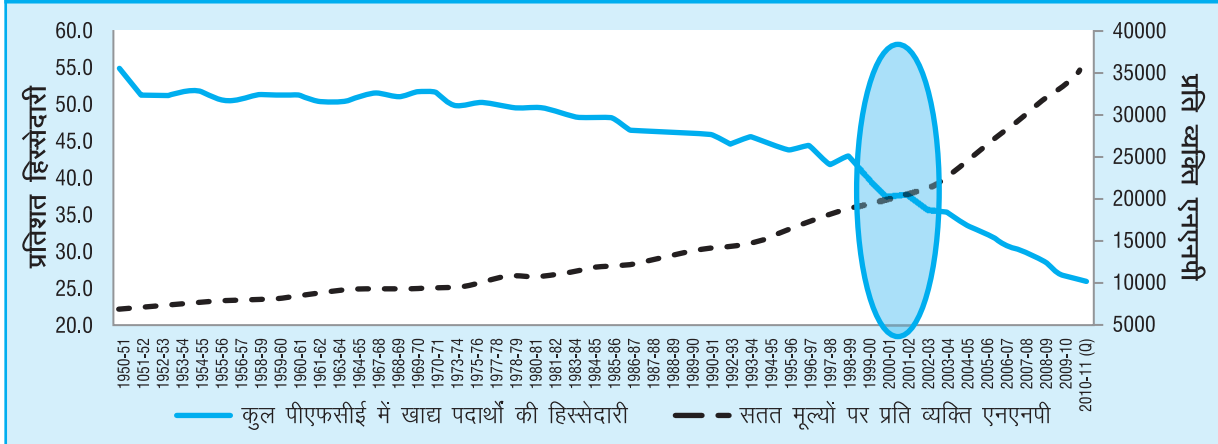
सारणी 4.9: खपत पैटर्न में बदलाव	2004-05 के मूल्यों (रुपये) पर प्रतिव्यक्ति औसत वार्षिक खपत					वृद्धि दरों का रुख		
	1950-91	1992-97	1997-02	2002-07	2007-12	1950-2012	1950-1991	1991-2012
	खाद्य वस्तुएं	4550	5803	6123	6066	6700	0.94	0.83
प्रोटीनयुक्त खाद्य वस्तुएं (दाल, दूध, अंडे, मांस और मछली)	1090	1654	1881	1962	2258	1.50	0.65	2.09
अनाज	1560	1705	1634	1578	1586	0.22	0.46	-0.55
अन्य	1900	2444	2608	2525	2856	1.10	1.25	0.92
गैर खाद्य वस्तुएं	4623	7206	9192	12015	17957	2.48	1.36	5.79
वस्त्र और जूते	555	951	1083	1312	2062	3.05	3.13	4.61
चिकित्सीय सुविधा तथा स्वास्थ्य सेवाएं	255	404	620	879	1172	3.64	3.46	7.09
परिवहन एवं संचार	523	1703	2402	3396	4796	5.57	4.41	7.09
अन्य गैर खाद्य वस्तुएं	3290	4147	5087	6428	9927	1.64	0.49	5.35
घरेलू बाजार में निजी अंतिम खपत व्यय (पीएफसीई)	9174	13009	15315	18081	24657	1.84	1.10	3.99
पीएफसीई में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी (%)	49.6	44.61	39.98	33.55	27.17			
कुल खाद्य खपत में खाद्य समूहों की हिस्सेदारी (प्रति व्यक्ति)	23.96	28.51	30.72	32.35	33.71			
प्रोटीनयुक्त खाद्य पदार्थ	34.29	29.39	26.68	26.01	23.67			
अन्य	41.75	42.11	42.60	41.63	42.63			

स्रोत: राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी (एएस) विविध संस्करण
टिप्पणी: योजना अवधियों के अनुरूप अंतिम 4 अवधियां

चित्र 4.8: खाद्य पदार्थों का निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) एवं प्रतिशत हिस्सेदारी



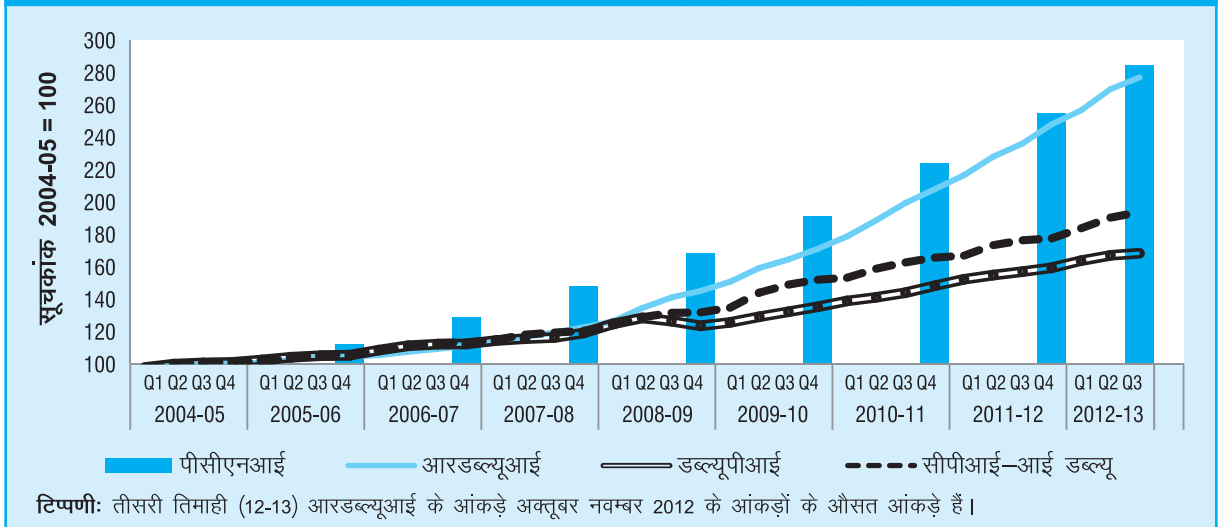
चित्र 4.9: कुल पीएफसीई में खाद्य पदार्थों की हिस्सेदारी बनाम प्रति व्यक्ति एनएनपी



प्रतिशत थी। खाद्य भिन्न वस्तुओं और सेवाओं के अन्तर्गत परिवहन और संचार; मनोरंजन और शिक्षा; चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल और विविध वस्तुओं और सेवाओं में औसत

वार्षिक वृद्धि क्रमशः 5.53 प्रतिशत, 3.97 प्रतिशत, 3.60 प्रतिशत, और 3.42 प्रतिशत थी। इन उपक्षेत्रों के व्यय में वृद्धि खाद्य पदार्थों की अपेक्षा उल्लेखनीय रूप से अधिक थी। सुधार पश्च अवधि

चित्र 4.10: प्रति व्यक्ति निवल राष्ट्रीय आय सूचकांक(पीसीएनआई), ग्रामीण मजदूरी सूचकांक (आरडब्ल्यूआई), डब्ल्यूपीआई एवं सीपीआई-आईडब्ल्यू



टिप्पणी: तीसरी तिमाही (12-13) आरडब्ल्यूआई के आंकड़े अक्टूबर नवम्बर 2012 के आंकड़ों के औसत आंकड़े हैं।

(1992-93 से 2010-11) में उपभोग व्यय में तीव्र बदलाव देखा गया।

4.20 आय में वृद्धि ने उपभोग में इस वांछित बदलाव को व्यवहार्य कर दिया। राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति के लिए समायोजित प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि बनी रही। ग्रामीण मजदूरी में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई। सांकेतिक सन्दर्भ में वर्ष 2008-09 से ग्रामीण मजदूरी में औसतन 18 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। इसी अवधि में मुद्रास्फीति समायोजित ग्रामीण मजदूरी में 7.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई (चित्र 4.10)

4.21 खाद्य और खाद्य भिन्न दोनों क्षेत्रों में उत्पादकों के लिए निवेश लागत जो खाद्य पदार्थों, चारा और अन्य निवेशों की कीमतें परिलक्षित होती है, में भी वृद्धि हुई है न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि, जहां किसानों को लाभ पहुंचाने की सुनिश्चितता के लिए आवश्यक है ने आधार मूल्य में बढ़ोतरी की है और निवेश मूल्यों की वृद्धि में भी योगदान किया है।

मूल्य दबाव के अन्तर्गत वस्तुएं और नीतिगत कदम

4.22 जैसा कि पहले भी इंगित किया गया था कुछ ही वस्तुओं ने मुद्रास्फीति को असंगत रूप से बढ़ाया। वर्ष 2012-13 की

दूसरी तिमाही में डब्ल्यू पी आई में 28.68 प्रतिशत के भारांश वाली 19 वस्तुओं (वस्तु समूह) ने कुल मुद्रास्फीति में 64.38 प्रतिशत का अंशदान किया (सारणी 4.10)। वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही अथवा तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में इन वस्तु समूह में प्रत्येक वस्तु का अंशदान उनके भारांश से 1.5 गुणा अधिक है।

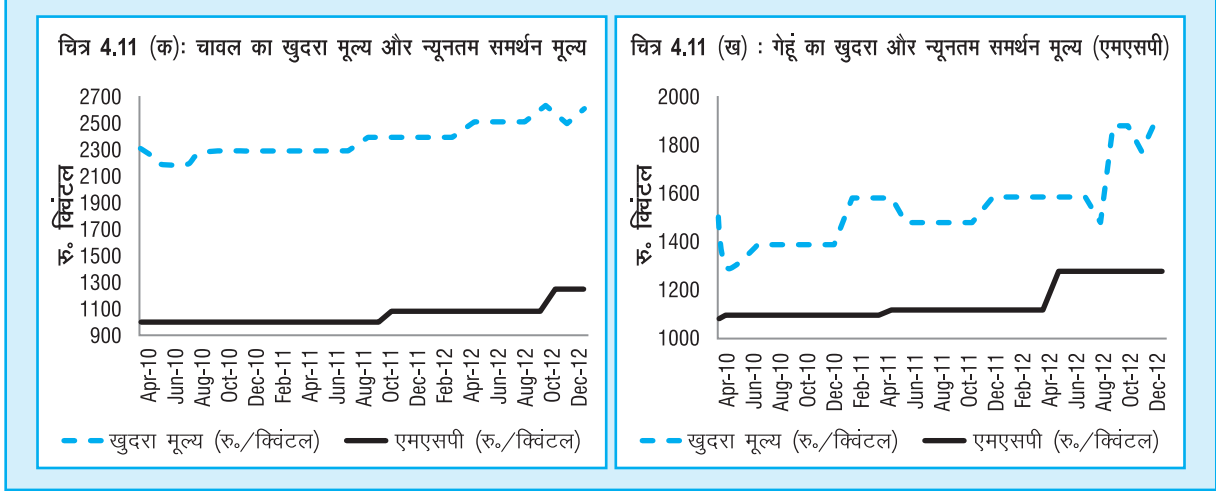
4.23 अन्य देशों की तरह भारत में भी मुद्रास्फीति मांग और आपूर्ति के बीच पारम्परिक असंतुलन से उत्पन्न हुई है। यह असंतुलन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है जिसके कारण कहीं महंगाई ज्यादा है तो कहीं कम। डीजल की तरह नियंत्रित मूल्यों में परिवर्तन से भी महंगाई बढ़ती है।

4.24 दो घटकों ने अनाजों की मुद्रास्फीति को बढ़ाया। गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि के अतिरिक्त ओपन मार्केट उपलब्धता और मांग खासतौर से गेहूं की मांग के बीच असंतुलन बना हुआ है। खासतौर से गेहूं की अधिप्राप्ति में तीव्र वृद्धि ने इसकी ओपन मार्केट उपलब्धता को घटाया है और इससे मूल्यवृद्धि को बल मिला। जहां सामान्य परिस्थितियों में अधिक

सारणी 4.10 हेडलाईन डब्ल्यू पी आई मुद्रास्फीति में भारांश योगदान: मदों को देखा जाए									
मुख्य समूह	भारांश	2010-11		2011-12			2012-13		
		वित्तीय वर्ष	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही (अ)
खाद्य उत्पाद	13.03	9.44	12.91	14.79	11.03	14.02	22.99	30.24	35.37
चावल	1.79	1.33	0.66	0.84	0.68	0.68	1.61	2.77	4.02
गेहूं	1.12	0.44	-0.01	-0.14	-0.52	-0.47	1.06	1.96	3.57
मक्का	0.22	0.27	0.84	0.59	0.44	0.62	0.29	0.41	0.75
चना	0.33	-0.06	0.25	0.82	1.77	1.89	2.44	2.96	1.95
आलू	0.20	-1.2	0.00	0.25	-0.38	-0.08	1.50	1.64	1.63
प्याज	0.18	0.79	0.20	0.76	-2.09	-3.40	-0.24	-0.65	0.74
मत्स्य (अन्तर्देशीय + समुन्द्रीय)	1.30	5.47	2.29	2.96	4.12	6.79	5.64	4.70	4.20
काली मिर्च	0.03	0.14	0.33	0.31	0.41	0.41	0.36	0.37	0.24
चाय (प्राथमिक + विनिर्माण)	0.80	0.04	0.94	0.31	-0.39	0.48	0.17	0.37	0.93
तिलहन + खाद्य तेल + खली	5.32	2.47	6.27	6.89	5.64	6.26	8.84	11.96	13.22
चीनी	1.74	-0.25	1.14	1.20	1.35	0.84	1.32	3.75	4.12
विनिर्माण उत्पाद	1.45	3.67	3.97	4.74	6.69	7.55	6.91	6.71	4.33
यूरिया-भिन्न उर्वरक	1.08	0.83	1.01	1.39	2.90	3.41	3.33	4.00	2.81
स्वर्ण, चांदी एवं स्वर्ण आभूषण	0.37	2.84	2.96	3.35	3.79	4.14	3.58	2.71	1.52
अन्य उत्पाद	14.2	18.3	23.01	24.37	30.23	38.8	28.65	23.65	24.68
अपरिष्कृत पेट्रोलियम	0.90	1.54	5.39	5.61	6.43	8.74	2.79	2.79	1.24
कोयला	2.09	1.49	3.38	3.29	3.48	7.12	4.68	4.41	4.72
गैर परिष्कृत खनिज तेल	3.04	6.63	10.92	10.20	13.73	13.18	9.01	7.84	3.17
विद्युत	3.45	1.59	0.08	-0.09	0.80	1.40	2.89	5.31	4.66
ज्वार बीज	0.05	0.04	0.25	0.50	0.68	2.40	3.99	1.28	0.85
हाईस्पीड डीजल	4.67	7.01	2.99	4.86	5.11	5.96	5.29	2.02	10.04

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालयअ: अनन्तिम

चित्र 4.11: चावल और गेहूं का एमएसपी और खुदरा मूल्य



अधिप्राप्ति प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं के स्टॉक के अनुपात को बढ़ाती है और मूल्य स्थिरता कायम कर सकती है, अपेक्षाकृत अधिक अधिप्राप्ति जिससे गैर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उपलब्धता में उल्लेखनीय रूप से कमी आई है से स्फीतिकारी दबाव पैदा हुए हैं। अपेक्षाकृत अधिक अंतरराष्ट्रीय कीमतों और कम हुई वैश्विक उपलब्धता ने अन्तरराष्ट्रीय कीमतों को वृद्धि की ओर धकेला है। इससे गेहूं के निर्यातों के लिए भी स्थिति उत्पन्न हुई और इसने गेहूं की निजी उपलब्धता को भी कम किया। जहां एफसीआई ने घरेलू उपभोग और निर्यात के लिए ओपन मार्केट विक्रय को अपने हाथ में लिया, इन संभालनों का घरेलू कीमतों पर अभी तक सीमित प्रभाव ही रहा शायद न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ बहुत कम गुजाइश है। गेहूं और चावल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि ने अपेक्षाकृत अधिक घरेलू मूल्यों में आंशिक तौर पर ही योगदान किया है। गेहूं के खुदरा मूल्यों और इसके न्यूनतम समर्थन मूल्य के बीच अन्तर जुलाई 2012 से ही बढ़ा है, चावल के मामले में भी यह अन्तर मार्च-अक्टूबर 2012 से और पुनः दिसम्बर 2012 से ही बढ़ा है (चित्र 4.11 (क) और 4.11 (ख))। दालों के मामले में भी कीमतों में तेजी मोटे तौर पर मांग और घरेलू उपलब्धता में चल रहे असंतुलन के कारण ही आयी है। आने वाले समय में दालों की मुद्रास्फीति पर अंकुश लगाने के लिए बेहतर उत्पादकता के जरिए दालों की आपूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता पड़ेगी।

4.25 विगत में सब्जियों की कीमतों में उतार-चढ़ाव रहा। मांग और आपूर्ति में असंतुलन के अलावा, अकुशल मध्यस्थता और फार्म टू माउथ के क्रियाकलापों के विभिन्न चरणों पर सब्जियों के मूल्यों में गिरावट, अधिक अस्थिरता और सभी स्थानों पर इसमें महत्वपूर्ण प्रकीर्ण ने कीमतों में बढ़ोतरी की। आपूर्ति

श्रृंखला में सुधार लाकर इन सबमें पर्याप्त रूप से कमी लाई जा सकती थी। किसान और उपभोक्ताओं के बीच बहुत अधिक मध्यस्थाओं की मौजूदगी और उनके कार्यकलापों समय विलंबता से मध्यस्थता लागतों और मूल्य लागतों में वृद्धि हुई। संगठित बाजार और अधिक मात्रा में निजी क्षेत्र की भागीदारी इस स्थिति में सुधार लाने के लिए आवश्यक है (बॉक्स 4.1 देखें)। लेकिन इसके लिए एपीएमसी विधान में सुधार लाने की आवश्यकता है। मुद्रास्फीति संबंधी अन्तरमंत्रालयी दल ने एपीएमसी के विनियम द्वारा किसानों को सग्राहकों और संसाधकों को सीधे ही बिक्री करने की स्वतन्त्रता देकर, सभी मण्डियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक निलामी स्थल बनाने की शुरुआत करके और एपीएमसी बाजार में लाइसेंस के स्थान पर बैंक गारंटियों के साथ पंजीकरण द्वारा विकारी खाद्य को इससे अलग रखने का सुझाव दिया था।

4.26 इन अनुशासित पंक्तियों के साथ कतिपय घटनाक्रम घटित हुए हैं। एकीकृत मूल्य श्रृंखला विकसित करने के लिए सरकार ने सब्जियों को बाजार शुल्क की उगाही से छूट देने की आवश्यकता पर जोर दिया। मध्यप्रदेश और प० बंगाल जैसे राज्यों ने हाल ही में फलों और सब्जियों पर लगने वाले बाजार शुल्क को माफ कर दिया। ऐसे लोग जिनके शुल्क माफ कर दिए गए हैं उनसे निजी क्षेत्र द्वारा आवश्यकता को मजबूत करने के घटनाक्रम में निवेश को प्रोत्साहित करने की आशा की जाती है। वायदा बाजार आयोग के साथ मिलकर कृषि मंत्रालय विभिन्न राज्यों में लगभग 1700 मंडियों में प्राइस टिकर बोर्ड संबंधी वायदा मूल्यों और इन स्थलों की पहचान को सुसाध्य बना रहा है। हाल ही में सरकार ने मल्टी ब्रांड खुदरा व्यापार में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को अनुमति दे दी है। इससे उपभोक्ता और किसानों को उन दोनों से जुड़े संभार संबंधी सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

बॉक्स 4.1 मुद्रास्फीति संबंधी अन्तर मंत्रालयी दल

प्रधानमंत्री की संस्तुति पर वित्त मंत्रालय के मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में एक अंतमंत्रालयी समूह (आयूएमजी) का गठन 2 फरवरी 2011 को किया गया जो विशेषकर प्राथमिक खाद्य वस्तुओं के सन्दर्भ में समग्र मुद्रास्फीति की समीक्षा करेगा। आज तक इस समूह की 15 फरवरी 2011 और 31 जनवरी 2012 के मध्य 8 बैठकें हुई हैं जिनमें मूल्य मानीटरिंग के सभी पहलुओं पर सूचना प्रणाली, मल्टीब्रान्ड खुदरा में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) एपीएमसी अधिनियम में सुधार, डीजल मूल्य निर्धारण के लिए नीतिगत उपाय और अन्य के साथ प्रोटीन युक्त उत्पादों में मुद्रास्फीति पर चर्चा की गई।

28 मई 2012 और 14 सितम्बर 2012 को आयोजित आईएमजी की छठी और सातवीं बैठकों में आईएमजी ने डीजल और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में विकृति को दूर करने के लिए नीतिगत उपायों पर चर्चा की। यह सुझाव दिया गया था कि डीजल पर सब्सिडी धीरे-धीरे प्रति लिटर के आधार पर निर्धारित की जाए और कीमतों में समायोजन मासिक आधार पर नियमित अन्तरालों पर, सतत रूप से किया जाए। यह भी उल्लेख किया गया कि डीजल की कीमतों में किसी भी फेरबदल का मुद्रास्फीति पर सीधे या परोक्ष प्रभाव पड़ेगा जो निरंतर बढ़ते स्तर पर रहता है। अतः इस फेरबदल में सुधार की जरूरत है।

आईएमजी ने प्राथमिक उत्पादों की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक दीर्घवधिक विश्वसनीय नीति की भी सिफारिश की खामियों रहित उत्पादकता स्तर में न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित प्रोत्साहन पर्याप्त नहीं होगा। उपयुक्त नियामक वातावरण में आनुवांशिक बीजों का प्रयोग करके दालों की उत्पादकता बढ़ाई जा सकती है।

4.27 पशु उत्पादों में विद्यमान अधिक मुद्रास्फीति आंशिक तौर पर उत्पादन केन्द्रों की क्षेत्रक संकेन्द्रण बढ़ती निवेश लागतों जिसने आधार मूल्यों में वृद्धि की तथा अपेक्षाकृत कम उत्पादकता के कारण रही है। जहां कुछ, मामलों में, उपलब्धता में वृद्धि हुए हैं विशेष रूप से अधिक लागत में/बाद में, सीमित संगठित विपणन (यहां तक कि दूध के मामले में यह कुल उत्पादित दूध का लगभग 15 प्रतिशत है) यथा पिछड़ी अवसंरचना कोल्ड चैन स्थापित नहीं की गई है। जिससे बर्बादी बढ़ी और गुणवत्ता घटी, की वजह से केन्द्रीय बजट 2012-13 में आपूर्ति बढ़ाने, और भण्डारण में सुधार तथा गोदाम सुविधा को बेहतर करने के लिए कई उपायों की घोषणा की गई है। सरकार ने 2011-12 में 300 करोड़ रूपए के आवंटन के साथ राष्ट्रीय प्रोटीन पूरक मिशन आरम्भ किया है। स्वच्छ जल मत्स्य पालन के अतिरिक्त तटीय मत्स्यपालन में मत्स्यपालन को और अधिक व्यापक करने के लिए 2012-13 में इस मिशन हेतु परिव्यय बढ़ाकर 500 करोड़ रूपए किया जा रहा है।

4.28 चीनी क घरेलू और वैश्विक कीमतों के भिन्न रूपों को देखते हुए चालू वर्ष के पूर्वाद्ध में चीनी की कीमतों में तेजी आई। जुलाई 2012 में कीमतों में वृद्धि आंशिक तौर पर आयात शुल्क लगाने के कारण हुई। जहां कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है (चीनी का 90 प्रतिशत उत्पादन बिक्री मुक्त है) एक नियमित निर्गम तंत्र उपलब्धता को प्रतिबन्धित करता है और कीमतों को विकृत करता है। केन्द्र सरकार देश में चीनी के उत्पादन, स्टॉक, चीनी की कीमतों और आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए घरेलू उपभोग के लिए प्रत्येक तिमाही में जारी की जाने वाली गैर-लेवी चीनी की प्रमात्रा तय करती है। हालांकि तंत्र मूल्य स्थिरता को सुनिश्चित करने के लिए है, दूसरी ओर चीनी की कीमतों में बहुत अधिक उतार-चढ़ाव दिखा। रंगराजन समिति ने चीनी उद्योग की समस्याओं का अध्ययन करने के बाद लेवी बाध्यताओं के साथ नियमित निर्गम तंत्र को अलग रखने और चीनी उद्योग को विनियमित करने की सिफारिश की है। ये सिफारिशें खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के अन्तर्गत विचाराधीन है।

4.29 कुछ प्राथमिक खाद्य वस्तुओं को छोड़कर, डब्ल्यूपीआर में शेष नये घटकों यूरिया और नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पाद पूरी तरह व्यापार योग्य है और इनमे से कोई भी उत्पाद नियमित मूल्य क्षेत्र में नहीं आता। इन उत्पादों की घरेलू कीमतें वैश्विक वस्तु कीमतों और इन उत्पादों की घरेलू उपलब्धता दोनों द्वारा नियंत्रित होती है। स्थिर रूपया और कम होती हुई वैश्विक कीमतें दोनों ही प्रभावशाली कारण हो सकते हैं जो इन उत्पादों की कीमतों को स्थिर रखने में महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

4.30 भारत में मुद्रास्फीति की तस्वीर और अधिक जटिल हो गई है क्योंकि उपभोग वस्तु समूह के खिसकने और पोटीन की पूर्ति तथा फल और सब्जियों जैसे लघु पोषकों में तीव्र प्रतिक्रिया नहीं हुई है। ब्याज दरें लोगों की प्राथमिकता बदलने का एक अनुपयुक्त तरिका है। यह इसलिए क्योंकि आर वी आई के लिए खाद्य पदार्थों के मूल्यों में वृद्धि के जरिए यह देखना तर्कसंगत रहेगा (जो एनएफएम मुद्रास्फीति पर संकेन्द्रण के जरिए पता चलेगा जिसमें खाद्य पदार्थों के मूल्य पर कम बल दिया जाता है। जहां यह सुनिश्चित करने की कोशिश करना कि खाद्य मुद्रास्फीति से मजदूरी प्रभावित न हो और महंगाई तय न करे तथापि खाद्य वस्तुएं कामगारों के उपभोग वस्तु समूह का एक बड़ा भाग होती हैं और अपेक्षाकृत अधिक खाद्य मूल्य अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी की मांग बढ़ाते हैं। क्या किया जा सकता है? और अधिक प्रोटीन की पूर्ति करने के लिए स्थितियां तैयार करने के सरकार के प्रयास (जिनका पहले भी उल्लेख किया जा चुका है) महत्वपूर्ण है। सरकार की हस्तक्षेप की प्रकृति जो उत्पादकता बढ़ने के बाद मजदूरी में वृद्धि करती को जुटाती है एक वेशकीमती खोज हो सकती है।

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए उपाय

4.31 मुद्रास्फीति सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों के लिए भिन्ना का प्रमुख कारण बनी हुई है। उन्होंने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अनेक उपाय किए हैं जिसका नीचे बॉक्स 4.2 में उल्लेख किया गया है।

बॉक्स 4.2 : मूल्य वृद्धि को नियंत्रित करने हेतु सरकार द्वारा किए गए अथवा प्रस्तावित उपाय**1. राजकोषीय उपाय**

- गेहूं, प्याज, दालों, अपरिष्कृत पामोलिन के लिए आयात शुल्क घटाकर शून्य किया गया और परिष्कृत व उद्जनित तेलों तथा वनस्पति तेलों के लिए आयात शुल्क घटाकर 7.5 प्रतिशत किया गया।
- सफेद तथा कच्ची शक्कर का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति 30.6.2012 तक की गई वर्तमान में 10 प्रतिशत आयात शुल्क लगाया गया।

2. प्रशासनिक उपाय

- आवश्यकतानुसार प्याज के निर्यात पर अल्पावधि के लिए रोक लगाई गई। प्याज का निर्यात न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) तंत्र के जरिए निर्धारित किया गया।
- चावल, उडद, तूर, ग्वार, गोंद तथा ग्वार बीज के वायदा व्यापार पर रोक लगाई गई।
- खाद्य तेलों (नारियल तेल तथा वन आधारित तेल के सिवाय) के 20,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता तक 5 किलो की क्षमता वाले मिश्रित उपभोक्ता पैकेटों में खाद्य तेलों (काबुली चना तथा जैविक दालें तथा मसूर की दाल प्रतिवर्ष 10000 टन की अधिकतम सीमा के सिवाय) के निर्यात पर रोक।
- चुनिंदा आवश्यक वस्तुओं जैसे दालें, खाद्य तेल तथा खाद्य तिहलनों तथा धान और चावल के मामलों में समय-समय पर भंडारण 30.11.2013 तक भण्डारण सीमा अधिरोपित की गई।

3. समाज के कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने मूल्य वृद्धि से बचाने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं।

- वर्ष 2002 से चावल (र 5.65 प्रति किलो ग्राम बी.पी.एल. के लिए और र 3 प्रति किलो ग्राम ए.ए.वाई. के लिए) तथा गेहूं (र 4.15 प्रति किलो ग्राम बी.पी.एल. और र 2 प्रति किलो ग्राम ए.ए.वाई. के लिए) के केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) को बनाए रखा गया।
- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत अधिक सब्सिडीकृत केंद्रीय निर्गम मूल्य (सीआईपी) पर प्रति परिवार/माह 35 कि.ग्रा. की दर से एएवाई और बीपीएल परिवारों के लिए 6.52 करोड़ रुपए का खाद्यान्न आवंटन किया जा रहा है।
- सरकार ने ओएमएस योजना के अंतर्गत चावल तथा गेहूं आवंटित किए।
- आयातित दाल आपूर्ति योजना जिसमें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए प्रति किलो पर 10 रुपए की सब्सिडी के साथ बीपीएल परिवारों को वितरित करने के लिए दाल आयातित करने पर विचार किया गया है नवम्बर 2008 से जून 2012 तक चलाई गई। सरकार ने वर्तमान वर्ष के शेष भाग हेतु बी.पी.एल. कार्डधारकों के लिए प्रतिमाह 20 रुपए प्रति कि.ग्रा. की सब्सिडी अंश का भुगतान देने का निर्णय लिया है। इसमें उन बी.पी.एल. लक्षित कार्डधारकों को शामिल किया जाएगा जिनका खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने अनुमान लगाया है।
- राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए 2008-09 से सब्सिडीकृत दरों पर आयातित खाद्य तेलों की वितरण योजना जिसमें प्रति किलो पर 15 रुपए की केंद्रीय सब्सिडी के साथ प्रति माह प्रति राशनकार्ड पर 1 लिटर की सब्सिडी दी गई है क्रियान्वित की गई है इस योजना को 30.09.2013 तक बढ़ा दिया गया है।

4. बजटीय तथा अन्य उपाय

पूर्ति बढ़ाने तथा भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए, केंद्रीय बजट 2012-13 में कई उपायों की घोषणा की गई है। सरकार ने 2011-12 में र 300 करोड़ के आबंटन से प्रोटीन अनुपूर्कों हेतु एक राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है। स्वच्छ जल मत्स्यपालन के अतिरिक्त तटीय मत्स्यपालन द्वारा मत्स्य उत्पादन का दायरा बढ़ाने हेतु 2012-13 में परिव्यय बढ़ाकर र 500 करोड़ किया जा रहा है। सरकार ने हाल ही में, मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इससे विक्रय तथा क्रय सुविधाओं में सुधार होने से उपभोक्ताओं तथा किसानों को मदद मिलेगी।

5. मौद्रिक उपाय

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भी मुद्रास्फीति को नियंत्रित रखने के लिए मार्च, 2012 से अक्टूबर, 2011 तक नीतिगत दरों में लगातार 13 बार 375 बी.पी.एस. की वृद्धि कर उचित कदम उठाए।

इन उपायों को वर्गीकृत किया गया है कुछ उपायों में वे जो मांग को नियंत्रित करते हैं (जैसाकि अपेक्षाकृत अधिक ब्याज दरें) वो, जो पूर्ति में सुधार लाते हैं (जैसे कि उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन), कमजोर उपभोक्ता को सुरक्षा प्रदान करते हैं (जैसे कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के लिए लक्षित सब्सिडी), वो सभी जो मूल्यवृद्धि का विरोध करते हैं (जैसे सब्सिडीकृत डीजल कीमतें) और वे उपाय जो बाजारों को बन्द करवा देते हैं जिससे कि मूल्य संकेत को छिपाया जा सके (जैसे कि वस्तु समूह

वायदा बाजारों को बंद करना) अथवा मूल्य वृद्धि को कम करना (जैसे कि निर्यात पर प्रतिबन्ध)

4.32 चूंकि मुद्रास्फीति स्थायी तौर पर बनी रही, अतः मांग और आपूर्ति के बीच उल्लेखनीय अंतर रहा। प्रभावी आपूर्ति को मांग के अनुरूप करने के लिए मांग में मामूली कमी करना एक अल्पकालिक प्रभावी उपाय हो सकता है किंतु गैर मुद्रास्फीति विकास की स्थिति प्राप्त करने के लिए एकमात्र दीर्घकालिक उपाय यह है कि आपूर्ति

में वृद्धि की जाए। खाद्य पदार्थों जैसी कुछ वस्तुओं जिनकी मांग दृढ़ होती है और संभवतः इसमें कमी लाना बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, के संबंध में आपूर्ति में वृद्धि करना ही प्राथमिक समाधान है। सरकार वित्तीय नियंत्रण के जरिए मांग पर नियंत्रण स्थापित कर सकती है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक उच्च नीतिगतदरों को लागू करके तथा नकदी को कठोर बनाकर ऐसा कर सकती है। इन उपायों से विकास की गति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा किंतु तथ्य यही है कि इन्हीं उपायों द्वारा मुद्रास्फीति पर नियंत्रण लगाया जा सकता है। यह देखते हुए कि भारत को आपूर्ति के संबंध में अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि निम्न कृषि उत्पादन, निम्न कोटि की अवसंरचना सुविधा, और एक सीमित कौशल आधार, अनेक पहल कारी। सरकारी उपायों के रूप में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए विकास अनुकूल तरीका यह है कि आपूर्ति पक्ष को सुदृढ़ बनाया जाए। और चूंकि आपूर्ति पक्ष के मजबूत होने तक समाज के अत्यधिक कमजोर तबकों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाने की संभावना है, अतः इस दिशा में कुछ लक्षित सहायता उपलब्ध कराना उचित है तथापि, व्यापक मात्रा में दी जाने वाली आर्थिक सहायता (जैसाकि डीजल सब्सिडी) से मूल्यों में कमी आती है, मांग में काफी अधिक वृद्धि होती है, राजकोषीय घाटा बढ़ता है तथा मुद्रास्फीति के विरुद्ध संघर्ष और अधिक कठोर हो जाता है। इन अल्पकालिक उपायों से बचने की आवश्यकता है। निर्यात पर आवधिक प्रतिबंध लगाना, टैरिफ लागू करना और हटाना तथा वायदा बाजारों को बार बार बंद करना भी समान रूप से उत्पादकतारोधी हैं। इन उपायों से उत्पादकों के लिए योजना तैयार करना कठिन हो जाता है, पारिश्रमिक में कमी करने से उत्पादन के लिए प्रोत्साहन घटता है तथा उत्पाद में वृद्धि निषिद्ध होती है जो मूल्यों पर अधिक स्थायी नियंत्रण स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं।

वैश्विक वस्तु समूह की कीमतों का रख

4.33 2008-09 की तीसरी तिमाही में वैश्विक वस्तुओं की कीमतें शीर्ष पर पहुंच गईं। इसके बाद कीमतों में गिरावट आनी शुरू हो गई और यह प्रवृत्ति जनवरी 2009 तक जारी रही, तब से कीमतों को अंतिम रूप दिया गया है। ऊर्जा तथा ऊर्जा भिन्न वस्तु समूह दोनों में कीमतों में वृद्धि 2010 तथा 2011 की पहली तिमाही में विशेष रूप से तीव्र थी। जहां 2011-12 की दूसरी तिमाही से ऊर्जा भिन्न कीमतें कम होनी शुरू हो गई थी और अधिकांश वस्तु समूह में मुद्रास्फीति पलटकर नकारात्मक होनी शुरू हो गई थी। बाद में ऊर्जा कीमतों में मामूली गिरावट होनी शुरू हो गई थी (सारणी 4.11 और चित्र 4.12)। चालू वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में ऊर्जा और ऊर्जा भिन्न कीमतों ने गिरावट दर्ज की। यह अंशतः आधार प्रभाव और आंशिक तौर पर कीमतों में गिरावट विशेषरूप से पेय-पदार्थों और मूल धातुओं की कीमतों में गिरावट के कारण थी।

4.34 वर्ष 2012-13 में खाद्यान्न खासतौर से गेहूं और मोटे अनाज के मामले में वैश्विक आपूर्ति में आई कमी से गेहूं और मक्का की कीमतें तेजी से बढ़ी और इसने अनाज के बड़े समूह को वस्तुसमूह सूचकांक की ओर धकेल दिया। वर्ष 2012-13 की दूसरी तिमाही में वसा और तेलों की कीमतों में भी खाद्य पदार्थों, चारा और ईंधन रिसाव के कारण वृद्धि देखी गई। वसा और तेल की कीमतें तत्पश्चात् कम होनी शुरू हो गई और तीसरी तिमाही में यह सीमाबद्ध दायरे में बनी रही।

4.35 अनुकूल स्फीतिकारी प्रवृत्ति जारी रहने की संभावना है और विश्व बैंक ने अपने जनवरी 2013 के वैश्विक आर्थिक संभावनाओं

सारणी 4.11: वैश्विक वस्तु समूह मुद्रास्फीति

मुख्य समूह	2010-11	2011-12	2011-12				2012-13		
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
सूचकांक (2005 = 100)									
ऊर्जा	154.5	193.0	197.6	187.2	186.6	200.8	183.7	183.2	182.1
ऊर्जा-भिन्न	188.4	202.8	217.2	212.3	188.8	192.9	189.3	191.0	186.9
पेय पदार्थ	194.1	196.2	218.7	210.7	183.7	171.7	162.7	169.7	160.8
गेहूं	189.7	236.8	245.8	245.4	229.3	226.8	227.1	263.9	258.9
वसा एवं तेल	202.2	216.7	227.1	220.4	202.5	216.9	231.1	250.2	221.9
मूल धातु	181.0	185.1	203.8	194.4	164.1	178.2	166.2	162.1	167.7
बहुमूल्य धातु	294.2	385.7	370.2	404.5	382.0	386.1	363.6	372.7	390.7
मुद्रास्फीति वर्षानुवर्ष (%)									
ऊर्जा	21.10	24.94	38.35	35.12	20.02	10.80	-7.05	-2.14	-2.41
ऊर्जा-भिन्न	24.82	7.63	32.70	24.52	-4.62	-12.93	-12.83	-10.02	-1.01
पेय पदार्थ	17.47	1.08	24.33	12.61	-5.09	-21.91	-25.61	-19.43	-12.46
अनाज	14.14	24.87	65.93	45.07	10.31	-2.87	-7.63	7.53	12.87
वसा एवं तेल	18.22	7.20	36.78	20.96	-7.78	-9.93	1.76	13.54	9.57
मूल धातु	30.08	2.27	27.41	19.35	-13.90	-15.40	-18.44	-16.59	2.16
बहुमूल्य धातु	31.02	31.12	41.02	50.20	21.75	16.61	-1.77	-7.85	2.27

स्रोत: वर्ल्ड बैंक पिंक शीट

बॉक्स 4.3 : वैश्विक वस्तु समूह मूल्य (पूर्वानुमान)

सारणी: संकेतिक मूल्य सूचकांक-वास्तविक और पूर्वानुमान (2005 - 100)

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	पूर्वानुमान 2012-13	परिवर्तन की दर (%) 2013-14
ऊर्जा	183	115	145	188	187	183	183	-2.6	0.1
ऊर्जा भिन्न	182	142	174	210	190	186	180	-2.0	-3.2
धातु	180	120	180	205	174	176	176	1.3	0.1
कृषि	171	149	170	209	194	188	180	-3.2	-4.4
खाद्य	186	156	170	210	212	205	192	-3.2	-6.4
अनाज	223	169	172	239	244	239	225	-2.1	-6.0
वसी और तेल	209	165	184	223	230	220	206	-4.2	-6.5
अन्य खाद्य	124	131	148	168	158	153	143	-3.1	-6.6
पेय पदार्थ	152	157	182	208	166	158	155	-4.7	-2.0
कच्चा माल	143	129	166	207	165	162	162	-2.2	0.4
उर्वरक	399	204	187	267	259	245	232	-5.6	-5.3
बहुमूल्य धातु	158	175	272	372	378	378	353	0.0	-6.7
कच्च तेल(डालर/विनिमन)	97	62	79	104	105	102	102	-2.9	0.2
स्वर्ण डालर	872	973	1225	1569	1670	1600	1550	-4.2	-3.1

स्रोत: वर्ल्ड बैंक

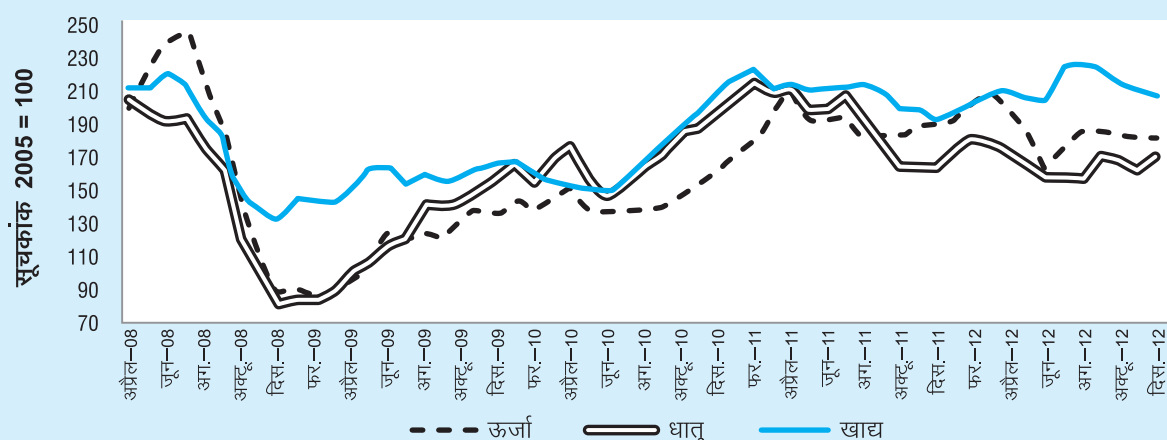
विश्व बैंक द्वारा वस्तु समूह में मुद्रास्फीति का स्थूल आकलन इस प्रकार किया गया है:

- वर्ष 2013 में तेल की सांकेतिक कीमतें औसतन 105.8 बिलियन डालर रहने की आशा है और वर्ष 2014 में ये मामूली सी बढ़कर 106.5 बिलियन अमरीकी डालर मुद्रास्फीति रहने की उम्मीद है चूंकि पूर्ति मांग में आई कमी के अनुरूप है। लंबे समय के बाद तेल की कीमतें पूर्ति बढ़ने, दक्षता लाभ और तेल से अलग उपकल्पन के कारण रूप में कम रहने का अनुमान है। जहां ओपेक का सीमित उत्पादन जारी रह सकता है, यह कीमतों को और अधिक नहीं बढ़ने देगा इस भय से तेल की वैकल्पिक पूर्तियों अथवा ऊर्जा स्रोतों की खोज की जाए जो लंबे समय से चल रही तेल की कीमतों में फेरबदल ला दे।

तांबे को छोड़कर समग्र धातु कीमतों के बढ़ने की उम्मीद है। बढ़ती विद्युत लागतों के कारण, वर्ष 2013 में एल्युमीनियम की कीमतें 15 प्रतिशत तक और अगले दो वर्षों तक 5 प्रतिशत तक और बढ़ सकती हैं। और यह तथ्य कि चालू कीमतों ने कुछ उत्पादकों को कम उत्पादन लागतों अथवा कम उत्पादन लागत की ओर धकेल दिया है। तांबे की कीमतें स्थानापन्न दबावों और मांग में आई कमी के कारण गिर सकती है। हालांकि धातु बाजार में कोई भौतिक अड़चन नहीं है, अयस्क के गिरते स्तर पर्यावरणीय मसले और बढ़ती ऊर्जा लागतों कीमतों में बढ़ोत्तरी कर सकती हैं।

- यह मानते हुए कि जैव ऊर्जा में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। वर्ष 2013 में कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरावट होने का अनुमान है। विशेषरूप से गेहूँ और मक्का की कीमतें वर्ष 2012 के स्तर से कम रहने की आशा है। पर्याप्त उपलब्धता के कारण सोयाबीन और पाम ऑयल की कीमतें कम रहने की उम्मीद है।

चित्र 4.12: वैश्विक जिन्स मूल्य सूचकांक



में ऊर्जा उत्पादों के लिए मुद्रास्फीति को कम करके ऊर्जा भिन्न कीमतों के न बढ़ने का पूर्वानुमान लगाया है (बॉक्स 4.3) अन्तरराष्ट्रीय तौर पर इस अनुकूल स्फीतिकारी संभावनाओं का भारत में वस्तु समूह कीमतों पर बहुत कम प्रभाव दिखेगा। औद्योगिक कच्चा माल और धातुओं की घरेलू कीमतें आमतौर पर अंतर्राष्ट्रीय रुख का अनुकरण करती हैं और कच्चे तेल और खाद्य तेलों के मामले में अधिक आयात निर्भरता के कारण अंतरराष्ट्रीय कीमतों का घरेलू कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है।

रजिडेक्स

4.36 ग्रामीणों का शहरी पलायन आर्थिक विकास का एक अनिवार्य हिस्सा है। संसाधनों का कम उत्पादन वाले ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक उत्पादकता वाले शहरी केन्द्रित क्रियाकलापों तक पुनः आबंटन किया जाता है। इसने बर्हिमुखता, आर्थिक गतिशीलता सुजित करने और अधिक तीव्र विकास के माध्यम से उत्पादकता में अधिक तीव्रता से विकास के साथ दुगना कर दिया है लेकिन ग्रामीण आवास का शहरी क्षेत्र में प्रवसन से नागरिक सुख सुविधाओं और आवास पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा है। यद्यपि बुनियादी सेवा प्रदान करने की लागत अधिक आवादी वाले शहरी क्षेत्रों में दूर-दूर बसी ग्रामीण क्षेत्र की आवादी में अपेक्षाकृत सस्ती है, नागरिक सुख सुविधाओं और आवास में निवेश किए जाने की आवश्यकता है। 1951 में शहरी आवादी का स्तर लगभग 17 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2011 में 30 प्रतिशत हो गया है और 2040 तक इस आंकड़े के 50 प्रतिशत तक पहुंचने की आशा है इसलिए संसाधन बढ़ाने के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा करने की जरूरत है।

4.37 अपर्याप्त आवासीय गतिविधियों तथा आवास संबंधी नव प्रवर्तन वित्तीय योजनाओं के अभाव ने शहरी मलिन वस्तियों की समस्या भी पैदा कर दी है हालिया स्थिति तक हमारे पास शहरी क्षेत्रों में आवासीय भवनों की कीमतों को दर्शाने वाला कोई इन्डैक्स नहीं था जिसका उपयोग आवास खरीदने का प्रमाणित कीमतों के आकलन में किया जा सके। एक पहल जो 2005-06 में की गई राष्ट्रीय आवासीय बैंक ने राष्ट्रीय स्तर पर एक सूचकांक तैयार करने की व्यवहार्यता की जांच करने के लिए एक प्रायोगिक योजना तैयार की जिसने आवासीय भवनों की कीमतों का हिसाब-किताब रखने के लिए रेंजिडेक्स की शुरुआत की रेंजिडेक्स की जुलाई 2007 में शुरुआत की गई इसमें 20 शहरों को शामिल किया गया और यह 2011-12 से तिमाही आधार पर अध्ययन किया जाता है और जारी किया जाता है।

4.38 सभी शहरों में आवासीय सम्पत्तियों की कीमतों में परिवर्तन की गति अलग-अलग होती है (सारणी 4.12) जहां हैदराबाद, जयपुर और बेंगलूर में 2007 की कीमतों के मुकाबले जुलाई-सितम्बर 2012 में कीमतों में गिरावट आई है पूना, भोपाल और चेन्नई में आवासीय कीमतों में शत प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि देखी गई है। दिल्ली, मुम्बई और कोलकाता जैसे तीन अन्य महानगरों में भी आवासीय कीमतें 75% से 100% के दायरे में रही हैं।

जीडीपी अपस्फीतिकारक

4.39 मंहगाई के लिए सीपीआई और डब्ल्यूपीआई प्रतिनिधिक उपाय है लेकिन कुल मिलाकर अर्थव्यवस्था के लिए सकल घरेलू उत्पाद अपस्फीतिकारक, उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं में मुद्रास्फीति के चाहे बाजार मूल्यों अथवा उत्पादन लागत पर अधिक उपयुक्त

सारणी 4.12 : 20 शहरों में आवासीय मूल्य सूचकांक में त्रैमासिक उतार-चढ़ाव

शहर	2011-12				2012-13		2007 से मूल्यों में परिवर्तन (%)
	अप्रैल-जून	जुलाई-सित.	अक्टू.-दिस.	जन.-मार्च.	अप्रैल-जून	जुलाई-सित.	
हैदराबाद	91	84	79	86	85	84	-15.7
जयपुर	64	65	64	80	78	85	-14.7
बेंगलूरु	92	93	100	92	100	98	-1.7
पटना	146	141	140	129	140	138	37.6
लखनऊ	160	154	165	164	171	175	75.0
दिल्ली	147	154	167	168	172	178	78.5
अहमदाबाद	169	163	167	164	174	180	79.7
कोलकाता	194	191	190	191	196	191	90.9
मुम्बई	181	194	193	190	197	198	98.0
पुणे	150	169	184	181	200	201	101.1
भोपाल	224	208	211	204	207	206	106.1
चेन्नई	248	271	296	304	309	312	212.0

स्रोत: नैशनल हाउसिंग बैंक

उपाय है। ये वैकल्पिक उपाय डब्ल्यूपीआई से मेल खाते हैं लेकिन सीपीआई-आईडब्ल्यू से कुछ हद तक भिन्न हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू के मामले में 2009-10 की दूसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में कोई खास कमी नहीं हुई है क्योंकि इस अवधि में खाद्य मुद्रास्फीति ज्यादातर अधिक रही।

मौद्रिक प्रबंधन

वर्ष 2011-12 के दौरान मौद्रिक घटनाक्रम

4.40 भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मूल मुद्रास्फीति को काबू करने और वृद्धि को सुसाध्य बनाने के दो ध्येयों पर केन्द्रित करना जारी रहा। (मौद्रिक नीति संचरण दर्शाने वाला चार्ट बॉक्स 4.4 में उपलब्ध है) जनवरी 2010 से अक्टूबर 2011 के दौरान बने मुद्रास्फीति के दबाव हेतु भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा कठोर मौद्रिक नीति अपनायी जानी अपेक्षित की। इस अवधि के दौरान भारतीय

रिजर्व बैंक ने पालिसी दर रेपो रेट) 4.75 प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत 375 बेसिस प्वाइंट बढ़ा दी। अप्रैल 2010 में मुद्रास्फीति 10.9 प्रतिशत के शिखरतम पहुंच गयी थी। अप्रैल 2012 में अप्रैल 2010 की तुलना में मुद्रास्फीति 10.9 प्रतिशत के शिखर से घटकर 7.6 प्रतिशत रह गयी तथापि आंतरिक एवं बाह्य स्रोतों से वृद्धि के प्रति बढ़ते जोखिम तथा कठोर मौद्रिक नीति के समक्ष सतत स्फीतिवारी दबाव में अप्रत्याशित रूप से तेजी से गिरावट में योग दिया। जबकि भारतीय रिजर्व बैंक के संतुलित वृद्धि तथा स्फीतिगति को नियंत्रित करने हेतु अक्टूबर 2011 से नीति में बदलाव किया। इससे नकदी स्थिति में सुधार लाने हेतु अप्रैल, 2012 में रेपो रेट में 50 बेसिस प्वाइंट तथा पुनः जनवरी 2013 में 25 बेसिस प्वाइंट तथा नकद आरसी अनुपात (सीआरआर तथा सांविधिक नकदी अनुपात (एसएलआर) में कमी आयी। (सारणी 4.13)

4.41 भारतीय रिजर्व बैंक के निर्धारण के अनुसार, वैश्विक अर्थव्यवस्था और वित्तीय स्थितियों किसी बाह्य वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था

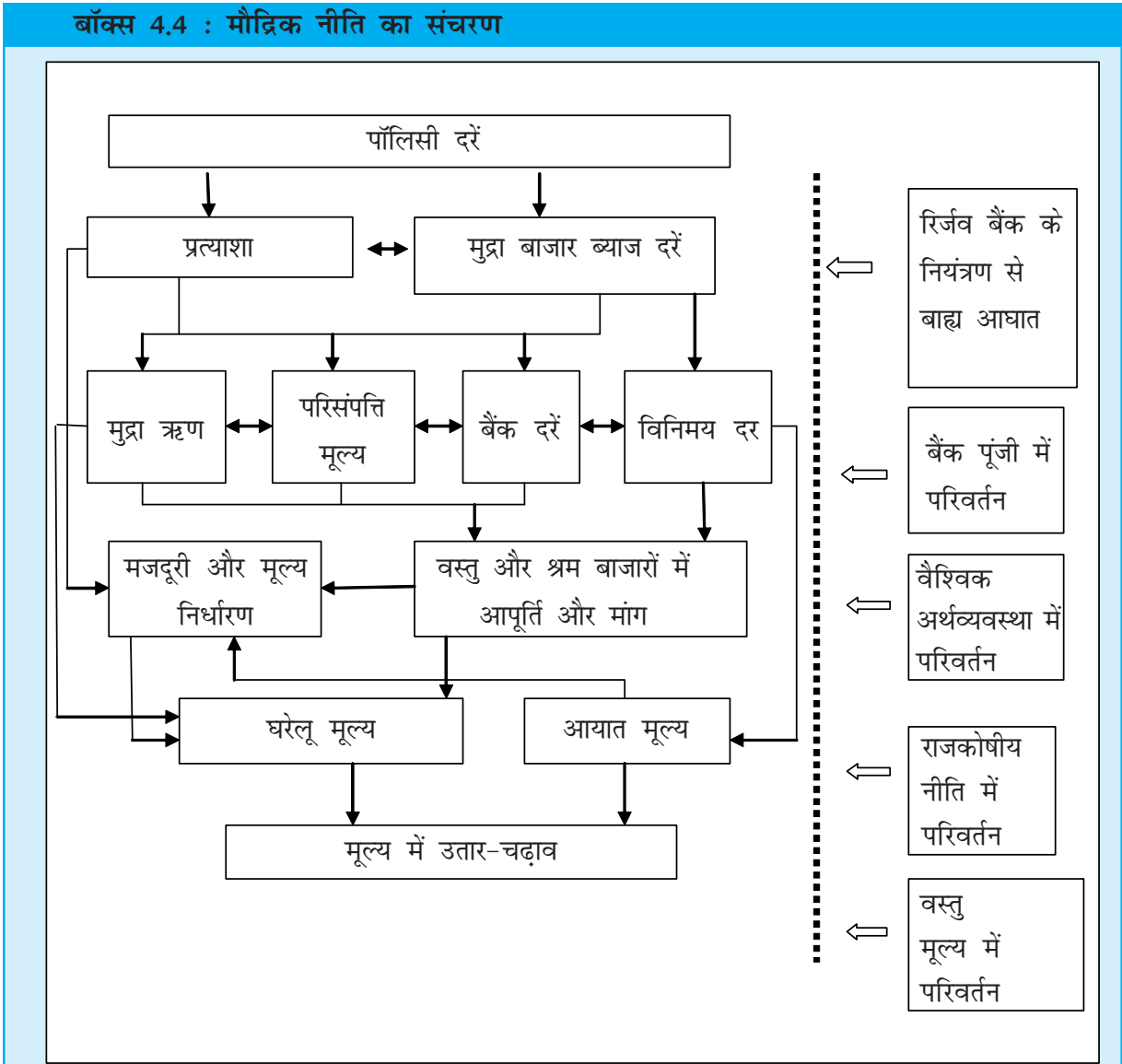
सारणी 4.13 : पालिसी दरों में संशोधन (प्रतिशत)

प्रभावी तिथि	रेपो रेट	रिवर्स रेपो रेट	सीआरआर	एसएलआर	एमएसएफ रेट*
2010-11					
20 अप्रैल 2010	5.25	3.75	5.75	25.00	
24 अप्रैल 2010	5.25	3.75	6.00	25.00	
2 जुलाई 2010	5.50	4.00	6.00	25.00	
27 जुलाई 2010	5.75	4.50	6.00	25.00	
16 सितं. 2010	6.00	5.00	6.00	25.00	
2 नव. 2010	6.25	5.25	6.00	25.00	
18 दिसं. 2010	6.25	5.25	6.00	24.00	
25 जनजन. 2011	6.50	5.50	6.00	24.00	
17 मार्च 2011	6.75	5.75	6.00	24.00	
2011-12					
3-मई-11	7.25	6.25	6.00	24.00	
9-मई-11	7.25	6.25	6.00	24.00	8.25
16 जून 2011	7.50	6.50	6.00	24.00	8.50
26 जुलाई 2011	8.00	7.00	6.00	24.00	9.00
16 सितं. 2011	8.25	7.25	6.00	24.00	9.25
25 अक्टू. 2011	8.50	7.50	6.00	24.00	9.50
28 जन. 2012	8.50	7.50	5.50	24.00	9.50
10 मार्च 2012	8.50	7.50	4.75	24.00	9.50
2012-13					
17 अप्रैल 2012	8.00	7.00	4.75	24.00	9.00
18 जून 2012	8.00	7.00	4.75	24.00	9.00
11 अगस्त 2012	8.00	7.00	4.75	23.00	9.00
22 सितं. 2012	8.00	7.00	4.50	23.00	9.00
03 नव. 2012	8.00	7.00	4.25	23.00	9.00
18 दिसं. 2012	8.00	7.00	4.25	23.00	9.00
29 जन. 2013	7.75	6.75	4.25	23.00	8.75
09 फर. 2013	7.75	6.75	4.00	23.00	8.75

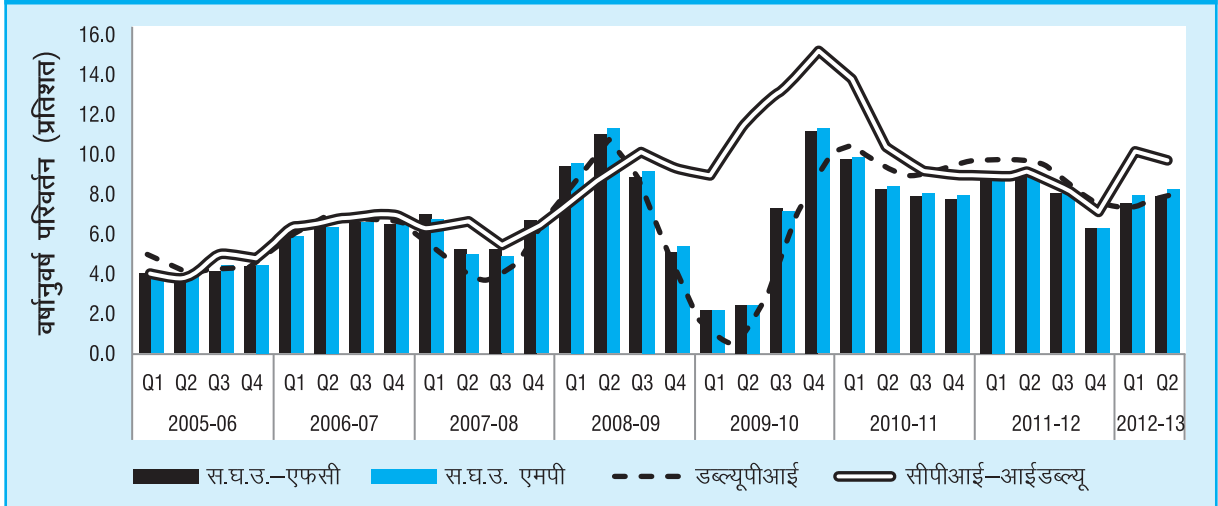
स्रोत: आरबीआई

टिप्पणी: एमएसएफ दिनांक 9 मई 2011 से आरंभ हुआ।

बॉक्स 4.4 : मौद्रिक नीति का संचरण



चित्र 4.13: सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर बनाम डब्ल्यूपीआई और सीपीआई-आईडब्ल्यू मुद्रास्फीति



को प्रेरित करने में लगातार कमजोर रही। दूसरी ओर आंतरिक तथा बाह्य स्फीतिवारी दबावों विशेषकर रुपए के घटते मूल्य ने व्यापार योग्य वस्तुओं पर दबाव अनुपात पॉलिमी दरों में कोई कमी कर सकता है। इसके अलावा उत्पादक क्षेत्रों में नकदी की विषम स्थितियां साख के पर्याप्त प्रवाह के जोखिम के रूप में उभरी। अतएव अप्रैल-दिसम्बर, 2012 के दौरान लगातार स्फीति जोखिम के कारण मौद्रिक नीति के लगातार सतर्क रुख अपनाया जिससे वृद्धि में सहयोग करने हेतु नकदी की सहणता से नीति दर में ठहराव आया। इस सतर्क मौद्रिक नीति को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भी अनुदान तथा बिगड़ती राजकोषीय परिस्थिति में आवश्यक समझा गया। तथापि सरकार ने सितम्बर 2012 में राजकोषीय समेकन का स्पष्ट परिभाषित मथ्यावधि राजकोषीय लक्ष्य की घोषणा की। इसने निवेशक बोध तक निवेश के पक्ष में वातावरण बनाने के प्रयास किए। जनवरी, 2013 में सरकार ने सितम्बर, 2012 में मध्यक्रम राजकोषीय घाटे को कम करने के प्रयासों के तहत डीजल मूल्यों में वृद्धि की घोषणा की। वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही में स्फीति कुछ सामान्य हुई तथा अपेक्षित राजकोषीय समेकन, चालू समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिति से मौद्रिक नीति को स्थान देता है।

4.42 चालू वर्ष में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति की स्थिति, वर्ष 2012-13 के व्यापक आर्थिक मानदंडों को इसके निरूपण पर आधारित थी। दिनांक 17, अप्रैल 2012 को जारी वर्ष 2012-13 के अपने मौद्रिक नीति विवरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने मार्च 2013 तक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 7.3% दर तथा थोक मूल्य सूचकांक के धीरे-धीरे 6.5% तक पहुंचने का अनुमान लगाया। 31 जुलाई, 2012 की इसकी पहली त्रैमासिक समीक्षा में, विकास का अनुमान नीचे की ओर बढ़कर

6.5 प्रतिशत हो गया, थोक मूल्य सूचकांक बढ़कर 7% हो गया तथा इस वृद्धि के अनुरूप उम्मीद की गई मुद्रास्फीति के अनुसार, यह एम. 3 और गैर-खाद्य क्रेडिट वृद्धि का क्रमशः 15% और 17% का लक्ष्य निर्धारित करता है। 13 अक्टूबर, 2012 के इसकी द्वितीय त्रैमासिक समीक्षा में भारतीय रिजर्व बैंक ने सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान को और कम करके 5.8% कर दिया और मुद्रास्फीति के अपने अनुमान को बढ़ाकर 7.5% कर दिया। एम. 3 और क्रेडिट वृद्धि के दर्शासूचक लक्ष्य नीचे की ओर बढ़कर क्रमशः 14% और 16% हो गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 29 जनवरी, 2013 को मौद्रिक नीति की अपनी तीसरी तिमाही समीक्षा में अपनी जी.डी.पी. के पूर्वानुमान को कम करके 5.5% कर दिया तथा मार्च 2013 तक मुद्रास्फीति का भी 6.8% तक की दर की उम्मीद व्यक्त की। इसके बाद एम. 3 की वृद्धि के अनुमान कम होकर 13% हो गए, यद्यपि क्रेडिट वृद्धि 16% पर रुकी रही। तथापि मौद्रिक मानदण्डों में उतार-चढ़ाव यही दर्शाती है कि स्थूल मुद्रा और क्रेडिट की वृद्धि, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दर्शाए गए स्तर से कम रही है।

4.43 चालू वर्ष में विकास के परिमार्जन और मुद्रास्फीति की लगभग 7-8% की दर ने कुल जमा पूंजी की वृद्धि को भी प्रभावित किया। जो वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही के औसत में 12.3% हो गई। बैंक क्रेडिट की वृद्धि दर पिछली दो तिमाहियों में 2011-12 की पहली तिमाही 1 21.7% से परिमार्जित होकर 16-17% हो गया। क्रेडिट में वृद्धि की अवेहलना करते हुए कम जमा पूंजी के कारण परिसम्पत्ति-देयता में अन्तर बढ़ गया है जो क्रेडिट-जमा अनुपात की बढ़ोत्तरी में दर्शायी गया है (सारणी 4.

सारणी 4.14: मुख्य मौद्रिक मानदण्डों में उतार-चढ़ाव(वर्षानुवर्ष वृद्धि दर प्रतिशत)

	2010-11	2011-12	2011-12				2012-13		
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
सकल घरेलू उत्पाद (बाजार की चालू दरों(818))	15.4	15.4	18.9	16.6	14.8	12.2	12.2	11.3	-
आरक्षित मुद्रा	21.5	14.1	17.6	15.9	14.7	8.7	7.3	6.5	4.3
स्थूल मुद्रा	16.2	15.8	17.3	16.8	15.4	13.8	14.2	13.6	12.6
औसत जमा	15.7	16.2	17.4	17.2	16.0	14.3	14.7	14.0	12.9
बैंक क्रेडिट	21.3	18.7	21.7	19.6	17.6	16.4	18.1	16.8	16.5
निवेश	9.4	14.3	10.3	15.5	15.5	15.7	16.1	14.4	15.2
मुद्रा की गति (एम.3/जी.डी.पी.)	1.28	1.27	1.22	1.20	1.31	1.35	1.20	1.17	-
मुद्रा गुणक (एम.3/एम.ओ.)	5.0	5.0	4.92	5.03	5.07	5.12	5.24	5.37	5.44
सी.डी. अनुपात (प्रतिशत)	73.3	74.7	74.3	73.5	74.3	76.4	76.5	75.4	76.7

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया

सारणी 4.15: आरक्षित मुद्रा के घटक और स्रोत

	2010-11	2010-12	2011-12				2012-13		
			पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
आरक्षित मुद्रा	21.5	14.1	17.6	15.9	14.7	8.7	7.3	6.5	4.3
आरक्षित मुद्रा के घटक									
करेंसी परिचालन में									
भारतीय रिजर्व बैंक के पास बैंकों की जमा राशि	19.2	14.1	17.1	14.6	12.8	12.3	12.3	13.3	11.7
करेंसी एमओएस का प्रतिशत	29.1	14.8	19.5	20.0	20.9	0.9	-6.4	-11.0	-15.5
आरक्षित मुद्रा के स्रोत	73.1	73.2	73.4	72.1	72.6	74.5	76.9	76.7	77.8
भा.रि.बैंक की निवल विदेशी विनियमन परिसम्पत्तियां									
जनता के प्रति मुद्रा देयताएं	0.9	11.9	9.1	11.1	19.1	8.2	14.4	9.0	1.6
भा.रि.बैंक की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	13.0	6.4	10.2	4.7	5.3	5.5	8.3	14.3	13.6
एम. के प्रतिशत के मुकाबले एफ.ई. परिसम्पत्तियां	-8.7	45.7	25.0	32.2	71.4	51.8	74.1	49.9	19.0
	107	105	100	106	111	102	106	108	108

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया

14) और पूंजी निर्माण की धीमा गति ने, सरकारी और अन्य प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र की निधियों का प्रवाह बढ़ा दिया है।

आरक्षित मुद्रा (एम.0):

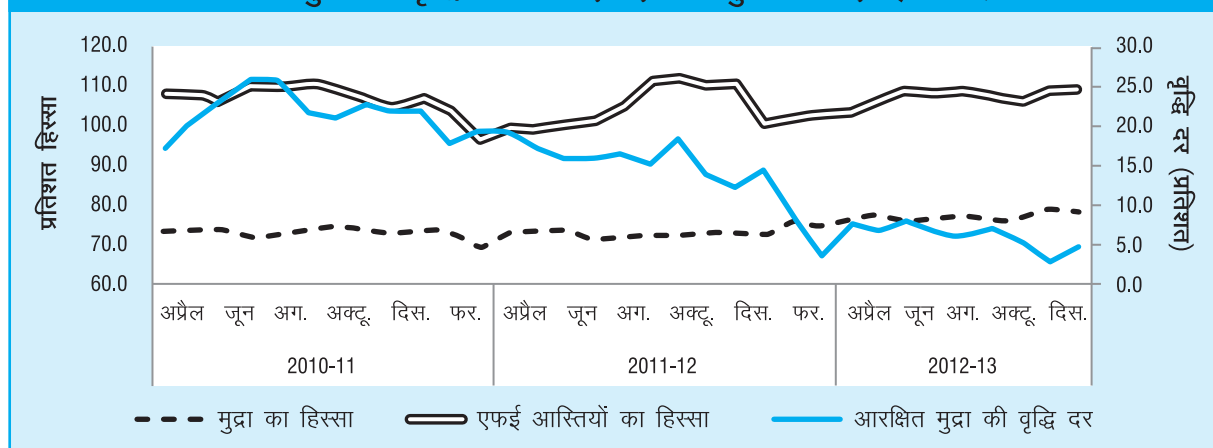
4.44 परिचलित मुद्रा और भारतीय रिजर्व बैंक (बैंकर और अन्य 1 के पास जमा मुद्रा सहित आरक्षित मुद्रा की वृद्धि दर वर्ष 2011-12 की पहली तिमाही के 17.6% के मुकाबले वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही की 4.3% हो गई। वर्ष 2011-12 के क्यू. 3 और वर्ष 2012-13 के क्यू. 3 के बीच आरक्षित मुद्रा में 2381 बिलियन रुपए की सम्पूर्ण धनराशि के स्रोतों के रूप में सरकार को आर. बी.आई का कुल क्रेडिट तथा आर.बी.आई की कुल परिसम्पत्ति में बढ़ोत्तरी से बेस मनी में बढ़ोत्तरी होती है। बेस मनी में बढ़ोत्तरी काफी हद तक रुक गई क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक की गैर-मौद्रिक देयताओं में बढ़ोत्तरी हो गई जोकि वर्ष 2011-12 में 1572 बिलियन से बढ़कर वर्तमान वर्ष के क्यू. 3 से 2011-12 के क्यू. 3 तक 3596 बिलियन रुपये हो गई। यद्यपि कुल विदेशी विनियमन

परिसम्पत्तियों बेस मनी के 100% से भी अधिक है। एन.एफ.ए. को अर्जित करने की वृद्धि दर पर्याप्त रूप से परिमार्जित हो गई है तथा यह वर्ष 2012-13 की तीसरी तिमाही 3 में 1.6% थी। वर्ष 2011-12 में और चालू वर्ष की दो तिमाहियों में भारतीय रिजर्व बैंक की कुल मौद्रिक देयताओं में काफी वृद्धि हुई। मुद्रा, बेस मनी का लगभग 3/4 हिस्सा थी।

स्थूल मुद्रा (एम. 3)

4.45 स्थूल मुद्रा की विकास दर न केवल भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सूचक विकास दर से कम थी अपितु इसमें पिछली 7 तिमाहियों के दौरान सतत और श्रंखला बद्ध कमी आई। सरकार और वाणिज्यिक क्षेत्र को कुल बैंक क्रेडिट समग्र एम. 3 विकास दर दिसम्बर 2012 में परिमार्जित होकर 11.2% हो गई। बैंकों में जमा कुल राशि, स्थूल मुद्रा का मुख्य घटक है जोकि कुल एम. 3 का 85% से अधिक है तथा यह अंश लगभग स्थिर चल रहा है। स्थूल मुद्रा के स्रोत हैं, ये दोनों मिलाकर वर्ष 2009-10 के 89% की स्थूल मुद्रा के मुकाबले वर्ष 2012-13 में 100% है। वाणिज्यिक

चित्र 4.14: आरक्षित मुद्रा की वृद्धि दर और एम.एम. में मुद्रा और एफई का हिस्सा

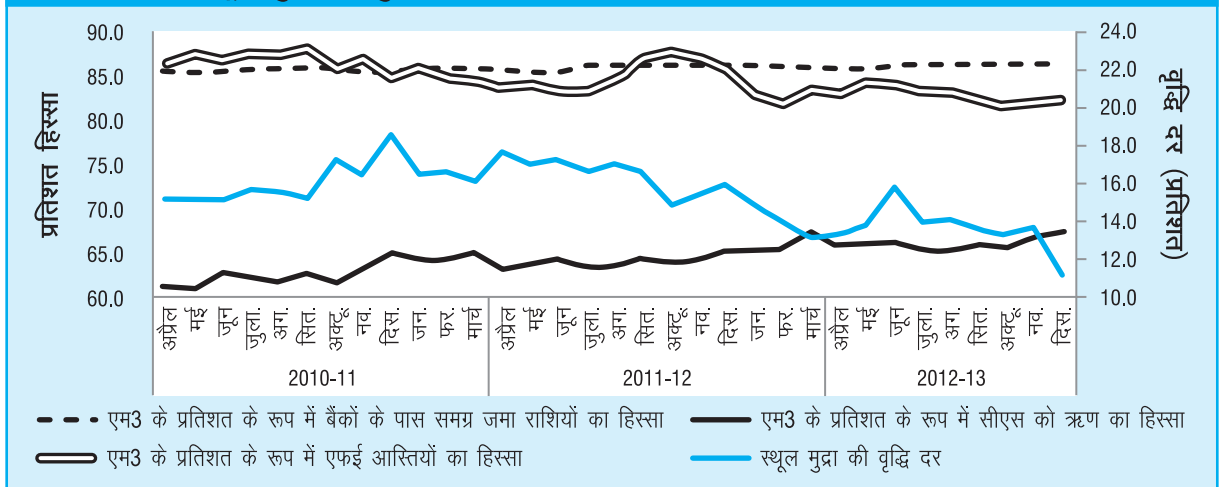


सारणी 4.16: स्थूल मुद्रा के घटक और स्रोत

रूप ए बिलियन में	2010-	2011-	2011-12				2012-13		
	11	12	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही	चौथी तिमाही	पहली तिमाही	दूसरी तिमाही	तीसरी तिमाही
मुद्रा स्टोक के घटक									
आम जनता के पास करेंसी	19.2	14.0	16.9	14.4	12.6	12.2	12.1	13.1	11.7
बैंकों के पास कुल जमा पूंजी	15.7	16.2	17.4	17.2	16.0	14.3	14.7	14.0	12.9
एम. 3 के प्रतिशत के रूप में बैंकों के पास कुल पूंजी	85.8	86.1	85.6	86.3	86.3	86.0	85.9	86.4	86.4
एम. 3 के स्रोत									
सरकार के पास बैंक क्रेडिट	21.5	21.8	18.9	22.1	23.1	23.1	22.1	20.2	17.7
वाणिज्यिक क्षेत्र का निवल एफ.ई.ए.	20.6	18.7	21.6	19.6	17.7	16.6	18.2	17.0	16.4
आम जनता के प्रति मुद्रा की निवल देयता	0.9	11.4	9.6	10.2	17.5	8.3	14.4	9.1	1.4
एम. 3 के % के रूप में एफ.ई. परिसम्पत्तियां	13.0	6.4	10.2	4.7	5.3	5.5	8.3	14.3	13.6
एम. 3 के % के रूप में वाणिज्यिक क्षेत्र का क्रेडिट	22.3	21.5	21.1	21.6	22.5	20.6	21.1	20.7	20.3
	63.0	64.6	63.9	63.8	64.5	66.1	66.1	65.5	66.6

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया

चित्रा 4.15: स्थूल मुद्रा - प्रमुख पैरामीटर



क्षेत्र के साथ बैंक क्रेडिट की विकास दर वर्ष 2011-12 के क्यू. 1 की 21.6% की औसत से घटकर वर्ष 2012-13 की क्यू. 3 में 16.4% हो गई है। सरकार के बैंक क्रेडिट की विकास दर, क्यू. 3 में 17.7% तक परिमार्जित होने से पूर्व वर्ष 2012-13 के क्यू. 2 तक 20% से अधिक स्तर पर स्थिर रही। तथापि बैंकिंग क्षेत्र की विदेशी विनियमन परिसम्पत्तियों के विकास में मंद गति की प्रवृत्ति देखी गई फिर भी स्थूल मुद्रा में उनका अंश लगभग 20% जारी रहा।

4.46 मार्च 2012 के अन्त में मुद्रा गुणक (एम. के संबंध में एम. 3 का अनुपात) 5.2 था जोकि मार्च 2011 से अधिक था जिसमें 2011-12 के क्यू. 4 में लगाई गई सी.आर.आर. की 125

बेसिस प्वाइंट वाली संचयी कटौती भी जुड़ी थी। चालू वर्ष 2012-13 के दौरान, मुद्रा गुणक, सी.आर.आर. कटौती को दिखाते हुए सामान्य तौर से काफी अधिक रहा है। 28 दिसम्बर, 2012 की स्थिति के अनुसार, पिछले वर्ष की तदनुसूची तारीख को 5.2 की तुलना में मुद्रा गुणक 5.5 था।

नकदी प्रबंधन

4.47 मौद्रिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था को पर्याप्त नकदी प्रदान करना है। तथापि नकदी का घाटा मौद्रिक नीति की स्थिति के त्वरित और सही दिशा के लिए आवश्यक समझा जाता है। मध्यावधि रुझान अत्यधिक नकदी घाटे के सूचक हैं

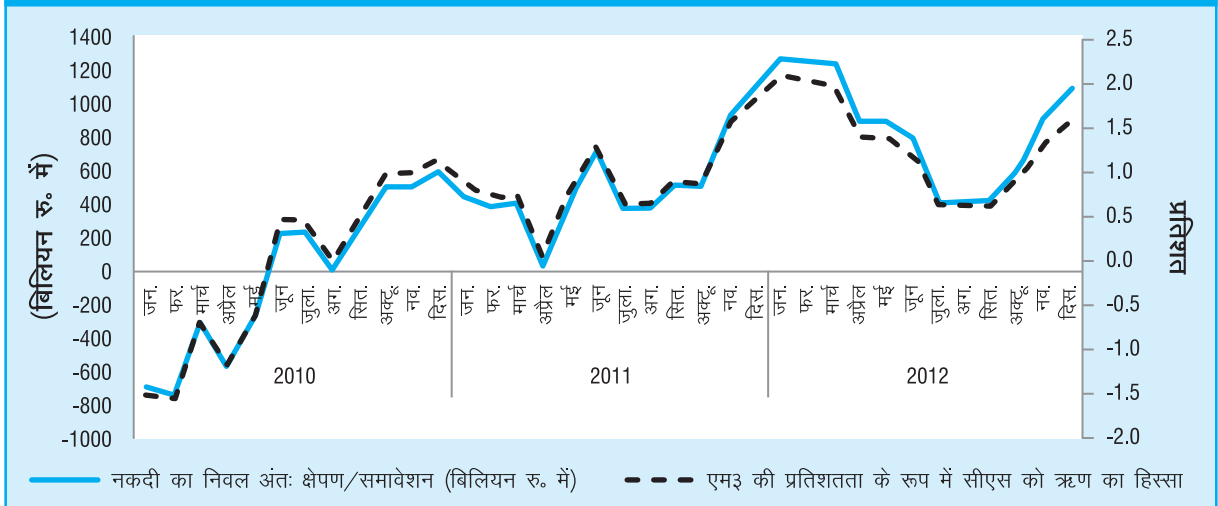
जिनमें नकदी का पुट देने की अपेक्षा होती है तथा यह डिमांड तथा सावधि देयताओं के कुल 1% के स्तर से अधिक होता है जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा उपयुक्त समझा जाता है। (आकृति 4.15) वर्ष 2011-12 के दौरान नवम्बर के मध्य तक नकदी की स्थिति ठीकठाक रही परन्तु वर्ष के बाद के हिस्से के दौरान दबाव बढ़ गया तथा नकदी समायोजन सुविधा के अन्तर्गत औसत कुल उधार के साथ मार्च 2012 में 1570 बिलियन पहुंच गया तथा 30 मार्च, 2012 को यह सबसे अधिक अर्थात् 2028 बिलियन भी हो गया। संरचनात्मक और संघर्षात्मक दोनों प्रकार के कारकों ने - भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा हस्तक्षेपित विदेशी विनियमन बाजार, क्रेडिट और जमा विकास दर में भिन्नता तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास सरकार नकदी संतुलन के होने से नकदी दबाव डाले। कठिन नकदी परिस्थितियों के प्रति अनुक्रिया करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कैश रिजर्व रेशों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से कम करने के साथ-साथ नवम्बर, 2011-मार्च 2012 के बीच कुल 1.3 ट्रिलियन के खुले बाजार के आपरेशन किए जिससे बैंकिंग प्रणाली में 0.8% ट्रिलियन की प्राथमिक नकदी का समावेश हुआ।

4.48 वर्ष 2012-13 की प्रथम छःमाही के दौरान नकदी की स्थिति धीरे-धीरे सुधरने लगी नकदी की स्थिति में परिवर्तन, सरकारी नकदी शेष में कमी, खुले बाजार आपरेशन के माध्यम से लगभग 860 बिलियन की नकदी का समावेश, प्रतिभूतियों का खरीदा जाना तथा बैंकों द्वारा निर्यात क्रेडिट पुनःवित्त सुविधा के अधिक प्रयोग करने के कारण हुआ। सांविधिक नकदी अनुपात में 1% की कटौती से भी बैंकों की नकदी में सुधार हुआ। दिसम्बर और अक्टूबर 2012 में 15 अक्टूबर, 2012 से कुल एलएएफ औसत उधार, जोकि डिमांड और मियादी देयताओं के 1% अर्थात् नकदी के अनुकूल स्तर से 1% अधिक था, की कुल औसत लेते हुए नकदी की स्थिति तथापि काफी गंभीर थी। मौजूदा व्यापक

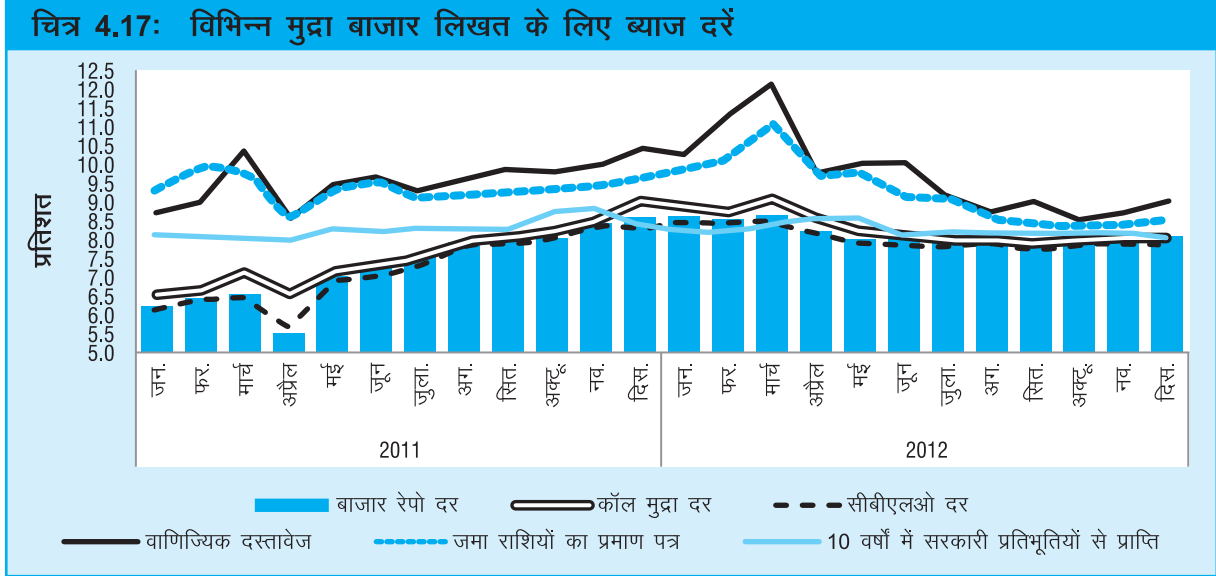
आर्थिक स्थिति के आधार पर रिजर्व बैंक 30 अक्टूबर, 2012 को उद्घोषित मौद्रिक नीति 2012-13 की द्वितीय तिमाही समीक्षा में) ने 3 नवम्बर, 2012 से शुरू होने वाले पखवाड़े से प्रभावी अनुसूची बैंकों के नकद रिजर्व अनुपात को उनके कुल डिमांड और मियादी देयताओं के 4.50 प्रतिशत से 25 आधार बिन्दु घटाते हुए 4.25 कर दिया। परिणामस्वरूप आधारीक नकदी के रूप में लगभग 175 बिलियन ₹ की धन राशि का बैंकिंग प्रणाली में समावेश कर दिया गया। एल.ए.एफ. के अन्तर्गत औसत दैनिक कुल नकदी, सितम्बर, 2012 की 520 बिलियन रुपये के मुकाबले अक्टूबर 2012 में 670 बिलियन रुपये हो गया। नकदी का संकट नवम्बर, 2012 में भी मौजूद रहा। एल.ए.एफ. के अन्तर्गत 940 बिलियन औसत दैनिक कुल नकदी का समावेश किया गया। तिमाही अग्रिम कर आऊटफ्लो के कारण नकदी का संकट दिसम्बर, 2012 के दूसरे पखवाड़ में और गहरा गया तथा माह के दौरान एल.ए.एफ. के अन्तर्गत दैनिक कुल नकदी का समावेश बढ़ाकर 1230 बिलियन रुपये कर दिया गया।

4.49 वर्ष 2012-13 की तृतीय तिमाही के अधिकांश समय नकदी की स्थिति रिजर्व बैंक के अनुकूल क्षेत्र से ऊपर रही। मौद्रिक नीति की स्थिति के अनुरूप और मौजूदा तथा विकसित होने वाली नकदी स्थितियों के चालू मूल्यांकन के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक ने 5 माह के अन्तराल के पश्चात् 4 दिसम्बर, 2012 खुला बाजार आपरेशन (सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी को खरीदा) फिर से शुरू कर दिए। 2012-13 के दौरान, खुले बाजार आपरेशन की नीलामी के अन्तर्गत अब तक (07 जनवरी, 2013 तक) 1060 बिलियन रुपए की कुल खरीद की गई। जबकि इस अवधि के दौरान बेनामी ट्रेडिंग प्लेटफार्म (एन०डी०एस०ओ०एम०) के माध्यम से कुल 228.7 बिलियन रुपए की खरीदारी की गई। यद्यपि रिजर्व बैंक ने सितम्बर और अक्टूबर 2012 में नकद आरक्षी अनुपात को

चित्र 4.16: नकदी का निवल अंतः क्षेपण/समावेशन



चित्र 4.17: विभिन्न मुद्रा बाजार लिखत के लिए ब्याज दरें



सफलपूर्वक कम कर दिया तथा नकदी को बढ़ाने के लिए दिसम्बर और जनवरी के दौरान 470 बिलियन रुपये की प्रणालीबद्ध नकदी का समावेश करते हुए खुले बाजार आपरेशन किए, और जनवरी में औसत कुल एल०ए०एफ० उधार 929 बिलियन रुपये था जो कि रिजर्व के अनुकूल स्तर से अधिक था। नकदी की यह तंगी, अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों की ओर क्रेडिट फ्लो को काफी कम कर सकती थी। प्रणाली में संरचनात्मक घाटे से प्रणाली में स्थाई आधारिक नकदी का समावेश करने की प्रबल स्थिति बन गई। तदनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की तृतीय तिमाही समीक्षा में नकदी आरक्षी अनुपात को 4.25% से कम करके 4% कर दिया जो कि 09 फरवरी, 2013 से प्रभावी हो गया। फरवरी के प्रथम सप्ताह के अंत तक एल०ए०एफ० का उधार कम होकर आर०बी०आई० के अनुकूल स्तर तक आ गया।

मुद्रा बाजार

4.50 मुद्रा बाजार 2012-13 के दौरान अब तक व्यवस्थित रही हैं। वार्षिक मौद्रिक नीति विवरण 2012-13 (अप्रैल 17, 2012 को जारी) की नीति (रेपो दर) में कटौती और नकदी की स्थितियों के परिणामस्वरूप, औसत दैनिक मांग बाजार दर, जून 2012 के 8.14% (मार्च 2012 में 9.17%) से घटकर सितम्बर 2012 में 7.92% हो गई। बाद के माह में मांग बाजार दरें संकीर्ण रेंज की तरफ उन्मुख हुई। (चित्र 4.16)। वाणिज्यिक दस्तावेज और जमा प्रमाण-पत्रों की ब्याज दरें, भी मार्च 2012 में सबसे अधिक थी तथा यह अन्य अधिकारकों की ब्याज दरों में परिमार्जन के अनुसार कम हो गई।

4.51 बैंक और प्राथमिक डीलर, सहयोगी सेगमेंट में उधार लेने वाले मुख्य समूह रहे जबकि सहयोगी उधार लेने और उधार देने वाले समूह में म्यूचुअल फंड मुख्य रूप से उधार देने के रूप में

अग्रणी रहे। अपितु हाल ही में, कुल उधार की राशि में म्यूचुअल फंड का अंश, मार्केट रेपो सेगमेंट में कम हो गया है और इस वर्ग में राष्ट्रीयकृत बैंक उधार देने वालों के मुख्य समूह के रूप में उभर कर सामने आए हैं। सहयोगी सेगमेंट तीव्र मुद्रा बाजार का अग्रणी बनता चला आ रहा है तथा 28 वित्त वर्ष के दौरान दिसम्बर, 2012) तक इसका अंश लगभग 7.8% था।

4.52 **जमाराशि सम्बन्धी प्रमाणपत्र**— जमाराशि सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों की धनराशि, 2012, मार्च अंत के 4195 बिलियन रुपये के मुकाबले दिसम्बर 2012, मध्य में कम होकर लगभग 3030 बिलियन हो गई जो कुल जारी प्रमाण-पत्रों में कमी दर्शाती है। कुल बकाया राशि (दिसम्बर 14, 2012 के) जमाराशि सम्बन्धी प्रमाण-पत्र जारी करने वाले बैंकों की कुल जमाराशि का 6.3% था तथा इसमें अन्तः बैंक का पर्याप्त अन्तर था। अप्रैल-दिसम्बर 2012 (14 दिसम्बर तक) के दौरान औसत पाक्षिक जारी प्रमाणपत्र की धनराशि पिछले वित्त वर्ष के दौरान तदनुसारी लगभग 344 बिलियन रुपये की राशि की तुलना में लगभग 293 बिलियन रही। जमाराशि के प्रमाणपत्रों की भारत औसत प्रभावी ब्याज दर मार्च 2012 के अन्त में 11.1% की दर से घट कर दिसम्बर 2012 के मध्य में 8.6% की दर तक पहुंच गयी।

4.53 वाणिज्यिक दस्तावेज वर्ष 2012-13 के दौरान वाणिज्यिक दस्तावेज बाजार में भी तेजी आयी थी तथा पाक्षिक रूप से जारी किए जाने वाले कागजात की औसत संख्या में पिछले वित्त वर्ष में इसी अवधि के दौरान 248 बिलियन से काफी अधिक बढ़कर 317 बिलियन (दिसम्बर 2012 के अन्त तक) हो गयी। कारपोरेट जगत द्वारा जारी जमा राशि प्रमाणपत्रों की बकाया राशि मार्च 2012 के अंत के 912 बिलियन रुपये से बढ़कर दिसम्बर 2012 के अंत तक 1818 बिलियन हो गई। कुल जारी किए गए जमा राशि प्रमाणपत्रों के सम्बन्ध में भारत औसत बट्टा दर (डब्ल्यू ए डी आर) मार्च 2012 की तुलना में दिसम्बर 2012 के अंत में 9.04 प्रतिशत तक घट गयी।

सारणी 4.17: मुद्रा बाजार का आकार

(₹ बिलियन में)

माह	एल॰ए॰एफ॰ की औसत		मांग मुद्रा				सी॰बी॰एल॰ओ॰		बकाया सीपी (अन्तिम माह के अन्तिम दिन)		बकाया सीपी (अन्तिम शक्रवार के अनुसार)	
	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012
	जनवरी	-929	-1292	78	173	115	89	448	280	1018	1499	3776
फरवरी	-786	-1405	104	142	132	122	423	331	1013	1618	4185	4029
मार्च	-810	-1574	113	175	151	112	432	380	803	912	4247	4195
अप्रैल	-188	-1029	134	250	144	143	562	377	1250	1310	4474	4448
मई	-546	-986	110	185	159	151	409	339	1212	1498	4333	4394
जून	-741	-913	116	152	167	180	413	376	1047	1258	4238	4252
जुलाई	-438	-481	115	146	117	173	410	382	1337	1732	4122	4155
अगस्त	-407	-462	113	129	148	183	391	459	1488	1879	4057	4030
सितम्बर	-559	-517	138	143	139	185	451	502	1446	1706	3835	3572
अक्टूबर	-541	-671	129	150	132	218	416	436	1688	1941	3859	3531
नवम्बर	-916	-941	110	141	133	207	329	368	1735	1994	3784	3066
दिसम्बर	-1167	-1231	149	142	99	147	265	398	1341	1818	4030	3031

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक आफ इंडिया

सी पी जारी करने में लीजिंग एंड फाइनेंस तथा विनिर्माता कंपनियों अग्रणी रही।

चुनौतियां तथा परिणाम

4.54 हैडलाइन डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति वर्तमान वित्तीय वर्ष में मंद रही तथा घटकर जनवरी 2013 में तीन सालों के न्यूनतम स्तर 6.62% पर पहुंच गयी और इसके साथ ही गैर-खाद्य विनिर्माण क्षेत्र में भी मंदी बनी रही। तथापि पिछले महीनों में सीबीई मुद्रास्फीति में वृद्धि का रुख रहा है जो मुख्य रूप से खाद्य पदार्थों के संबंध में उच्च मुद्रास्फीति के कारण हुआ है जिसके फलस्वरूप डब्ल्यूपीआई और सीपीआई के बीच अन्तराल बढ़ा है। पिछले वर्ष से भिन्न जबकि खाद्य पदार्थों के मूल्यों में मुद्रास्फीति मुख्य रूप से उच्च प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों में हुई वृद्धि के द्वारा प्रेरित थी, इस वर्ष अनाज के संबंध में दबाव बढ़ रहा है। दूसरी ओर दूध तथा अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थों के मूल्यों में गिरावट का रुख रहा है। हाल में जनवरी 2012 में प्याज के मूल्यों में हुई वृद्धि तथा डीजल के मूल्यों में संशोधन के कारण हैडलाइन मुद्रास्फीति पर कुछ दबाव पड़ सकता है। तथापि, गैर खाद्य विनिर्माण क्षेत्र एवं वैश्विक जिंस मूल्यों में कमी आने के फलस्वरूप मार्च 2013 में डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में 6.2 से 6.5 प्रतिशत तक की कमी होने की आशा है।

4.55 वर्तमान वर्ष में लगभग सभी प्रमुख उन्नत तथा उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति कम हुई है। प्रमुख उन्नत तथा विकासशील देशों द्वारा निरन्तर नीतिगत उपाय किये जाने के

सकारात्मक प्रभाव के फलस्वरूप मुद्रास्फीति संबंधी प्रत्याशाओं के लिए अधिक जोखिम उत्पन्न हो सकता है तथा मुद्रास्फीति पूर्वानुमानों के लिए ऊर्ध्वमुखी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। तथापि उल्पावधि में ही कमजोर वृद्धि की उम्मीद को देखते हुए नीति में नरमी लाने से मुद्रास्फीति में उछाल आने की संभावना नहीं है तथा मुद्रास्फीति संबंधी अनुमान मौजूदा लक्षित मुद्रास्फीति दरों के आसपास रहने की आशा है।

4.56 विश्व बैंक के वैश्विक आर्थिक अनुमानों के अनुसार धातुओं को छोड़कर अधिकांश वैश्विक जिंसों के मूल्य में 2013-2014 में और अधिक कमी आने की संभावना है। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर मुद्रास्फीति में नरमी आने की प्रत्याशाओं के परिणामस्वरूप घरेलू मूल्यों पर संयतकारी प्रभाव पड़ेगा। यह देखते हुए कि भारत को अपूर्ति पक्ष पर अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जल्दी ही मांग में मामूली कमी लायी जा सकती है तथा मांग आपूर्ति के बीच संतुलन स्थापित करना एक प्रभावी उपकरण सिद्ध होगा। तथापि आगे चलकर आपूर्ति में सुधार लाने के लिए उपाय करना मुद्रास्फीति रहित विकास को प्राप्त करने का एक मात्र तरीका है।

4.57 भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति के द्वारा मुद्रास्फीति पर रोक लगाने तथा विकास को सुकर बनाने के दोहरे उद्देश्यों पर निरन्तर बल देता रहा है। विदेशी तथा साथ ही घरेलू स्रोतों तथा सतत मुद्रास्फीति दबाव को देखते हुए कठोर मौद्रिक नीति के कारण वृद्धि के मार्ग के बढ़ते हुए जोखिमों के कारण अर्थव्यवस्था में आशातीत तेज गति से गिरावट आयी है। वर्ष

2012-13 की तीसरी तिमाही में मुद्रास्फीति में कुछ मंदी आयी है तथा प्रत्याशित वित्तीय सुदृढीकरण से अधिक उपयोगी मौद्रिक नीति के मार्ग प्रशस्त हुआ है। इसके अतिरिक्त, निम्न कोटि की आपूर्ति अनुक्रियाओं के हिस्से के कारण सृजित हो रही मुद्रास्फीति के एक

उल्लेखनीय भाग को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की नीतिगत पहल में आगे और बदलाव लाना तथा ऋण की उपलब्धता में सुधार लाना तथा ऋण तक अभिगम में सुधार लाना एवं उसकी लागत का आधुनिकीकरण वांछनीय होगा।